राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 39 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, सोमवार ,09 अगस्त 2021 , मूल्य रु. 1.50

संक्षिप्त समाचार

केंद्र सरकार का कोविन अभियान प्रशंसनीय : थरूर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वैश्विक महामारी कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए के देश में टीकाकरण का अभियान चल रहा है। अब तक देशभर में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान को अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी सराहा है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए शुरू किए गए कोविन के आलोचकों में से एक कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अब उसकी तरीफ की है।

देवी पार्वती मंदिर का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वादश ज्योतिलिंगों में प्रथम स्मरणीय बाबा सोमनाथ की अर्द्धशक्ति देवी पार्वती मंदिर का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। मंदिर के शिलान्यास के साथ ही पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर परिसर के चारों ओर बनाए गए परिपथ का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी खुद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सोमनाथ मंदिर परिसर में 21 करोड़ रुपए की लागत से सफेद संगमरमर से बनने वाले मां पार्वती के मंदिर का शुभारंभ 9 अगस्त को अमांत श्रावण मास की शुरूआत से हो सकता है। उल्लेखनीय है कि मंदिर ने कई बार विध्वंस देखा है लेकिन आज भी इसकी शोभा कम नहीं हुई है।

कोरोना मामले बढ़ने से बीजिंग में लगाया यात्रा प्रतिबंध

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बीजिंग के कुछ क्षेत्रों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सरकार ने इस क्षेत्र में यात्रा प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत मध्यम या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लोग जो बीजिंग लौटने की योजना बना रहे हैं, उन्हें हवाई और रेलवे सेवाओं के लिए टिकट खरीदने से रोका जाएगा। बीजिंग के अधिकारियों ने कहा कि जो लोग अभी भी मध्यम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं, उनके लिए स्वास्थ्य कोड पीले रंग में समायोजित किए जाएंगे। वहीं जिन्हें हरे रंग का स्वास्थ्य कोड दिया जाएगा उन्हें बीजिंग आने की अनुमति होगी।

कार्टून

समुद्री सुरक्षा पर परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा पर एक खुली परिचर्चा की डिजिटल माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। भारत इस साल अगस्त महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। एक अगस्त से भारत ने यह जिम्मेदारी संभाल भी ली है।

परिचर्चा का विषय समुद्री सुरक्षा बढ़ाना- अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के रखरखाव के लिए एक मामला होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि इस परिचर्चा में यूएनएसी के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और वहां की सरकारों के शामिल होने की संभावना है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी और प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के भी शामिल होने की संभावना है।

पीएमओ ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इस खुली परिचर्चा के केंद्र में समुद्री अपराध और असुरक्षा तथा इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना होगा। पीएमओ ने बताया कि यूएनएससी ने समुद्री सुरक्षा और समुद्री अपराध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और कई प्रस्ताव पारित किए हैं। हालांकि, यह पहली बार होगा कि समुद्री सुरक्षा पर उच्च स्तरीय और खुली चर्चा गहन तरीके से होगी।

पीएमओ ने कहा, कोई एक देश समुद्री सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की चिंता नहीं कर सकता लिहाजा यूएनएससी में इसे व्यापक विषय के रूप में आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा में एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, जिससे वैध समुद्री गतिविधियों की रक्षा हो सके और साथ ही समुद्री क्षेत्र के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटा जा सके।

आज पीएम मोदी किसानों के खाते में भेजेंगे 2000 रुपए

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत किसानों को अगली किस्त 9 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में इसकी सूचना दी गई है। इससे 9.75 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अकाउंट में हस्तांतरित की जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी किसानों के साथ बातचीत करेंगे और राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि पीएम-किसान योजना के तहत किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। ये 2000 रुपये की तीन समान किश्तों में सीधे बैंक अकाउंट में हस्तांतरित किए जाते हैं। इस योजना के जरिए अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसान परिवारों को भेजी जा चुकी है।

येदियुरप्पा नहीं चाहते हैं कैबिनेट पद का दर्जा

बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से अनुरोध किया कि वह उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने वाले आदेश को वापस लें। येदियुरप्पा ने बोम्मई को लिखे पत्र में कहा, मैं आपसे मुझे सिर्फ वह सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं, जो एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराई जाती हैं और मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने वाले आदेश को वापस लें। इस पत्र की प्रति मीडिया को उपलब्ध कराई गई। बोम्मई ने शनिवार को आदेश दिया था कि येदियुरप्पा को वैसी ही सुविधाएं दी जाएं, जो एक मंत्री को दी जाती हैं।

येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसी दिन कार्यालय में उनके कार्यकाल को दो साल भी पूरे हुए थे। इस्तीफे के एक दिन बाद, येदियुरप्पा ने भाजपा विधायक दल की बैठक में बोम्मई का नाम नेता के तौर पर प्रस्तावित किया था, जिसे सभी ने स्वीकार किया था। इसके बाद बोम्मई ने 28 जुलाई को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी।

पीएम केयर फंड की वैधानिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

नई दिल्ली। पीएम केयर फंड की वैधानिकता को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। दिव्यापाल सिंह ने यह याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजेश ईनामदार सहित 6 वरिष्ठ वकीलों द्वारा यह याचिका पेश की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहिले भी पीएम केयर फंड को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। उसमें सरकार द्वारा सही जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में, याचिकाकर्ता ने पीएम केयर फंड की वैधानिकता को चुनौती दी है। पीएम केयर फंड में सरकारी योजनाओं, कंपनियों के सीएसआर फंड, सांसदों एवं मंत्रियों के कोटे से प्राप्त राशि तथा दान के रुप में अरबों रुप्या का फंड एकत्रित हुआ है। इसके बाद भी सूचना अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने, पीएम केयर फंड को लेकर जो गोपनीयता बरती जा रही है। पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटीलेटर का खराब होना, जिस डाक्टर ने सबसे पहिले वेंटिलेटर खराब होने की रिपोर्ट सार्वजनिक की। उस पर निलंबन की कार्यवाही करने, पीएम केयर फंड में जारी राशि को सार्वजनिक नहीं करने तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें होने पर कार्यवाही नहीं होने जैसे तथ्यों के आधार पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पीएम केयर फंड को लेकर पिछले 1 वर्ष में जिस तरह के आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं। पीएम केयर फंड के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सूचना अधिकार कानून के दायरे से बाहर होने तथा सीएजी आडिट दायरे से बाहर होने के कारण यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कोविड के दौरान वेंटीलेकर एवं ऑक्सीजन प्लांट को लेकर आर्थिक गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगे हैं।

हेलमंद हवाई हमले में मारे गए 112 तालिबानों में 30 पाकिस्तानी लड़ाके : अफगानिस्तान

काबुल, (एजेंसी)। अफगानिस्तान में तालिबानों को मदद मुहैया कराने में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अफगान सरकार ने बड़ा खुलासा किया। पाकिस्तान की भूमिका अब खुलकर सामने आ चुकी है। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय ने पाक की पोल खोलते हुए बताया कि तालिबान के खिलाफ हमले में मारे गए 112 तालिबानियों में कम से कम 30 पाकिस्तानी लड़ाके भी शामिल हैं। ये आतंकी अल-कायदा आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि 6 अगस्त को लश्करगाह शहर में हुए हवाई हमले में कुल 112 तालिबान आतंकवादी मारे गए। अफगान रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि हेलमंद प्रांतीय केंद्र के बाहरी इलाके में किए गए हवाई हमले में 31 लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा दुश्मनों के कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और भारी मात्रा में हथियार भी नष्ट किए गए हैं। हाल ही में अफगान सेना ने तालिबान पर कारवाई के दौरान पाकिस्तान सेना के एक सैन्य अधिकारी को मार गिराया था जो तालिबान की ओर से लड़ाई लीड कर रहे थे। अफगानिस्तान ने पाक पर लगातार आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सरकार अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह देती है और तालिबान का समर्थन करती है।

संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत गुलाम इसाकजई ने 6 अगस्त को कहा था, अफगानिस्तान अपने दावे के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सबूत देने को तैयार है कि पाकिस्तान, तालिबान को लगातार सपोर्ट कर रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आतंकी संगठनों से संबंध नहीं तोड़ने के लिए पाकिस्तान को लताड़ा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, तालिबान के सपोर्ट में हजारों लड़ाके भेज रहा है। राष्ट्रपति गनी ने लंबे समय से इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान के नाम से छद्म युद्ध से लड़ता है।

नई पैकेजिंग के साथ रीलॉन्च होगी उज्ज्वला योजना, इस बार सिलेंडर और गैस स्टोव भी मुफ्त

नई दिल्ली। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गरीब परिवारों को फ्री एलपीजी कनेक्शन देने की योजना उज्ज्वला को केंद्र सरकार नई पैकेजिंग के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले रीलॉन्च करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरूआत करेंगे। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थी को गैस कनेक्शन के साथ-साथ स्टोव और पहली बार भरा हुआ सिलेंडर भी फ्री मिलेगा।

साल 2017 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में केंद्र की उज्ज्वला योजना की काफी चर्चा हुई थी और बीजेपी की बड़ी जीत का श्रेय इसे भी दिया गया था। हालांकि, उज्ज्वला के पहले संस्करण में सरकार सिर्फ एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए (डिपॉडिट मनी) की राशि की आर्थिक सहायता देती थी। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले परिवार स्टोव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज के लोन ले सकते थे।

उज्ज्वला 2.0 के तहत केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में लगभग एक करोड़ गैस कनेक्शन गरीबों को मुफ्त में बांटेगी। आज से लगभग पांच साल पहले, यूपी चुनावों से पहले, पीएम मोदी ने 1 मई, 2016 को राज्य के बलिया जिले में इस योजना का पहला संस्करण (उज्ज्वला 1.0) लॉन्च किया था। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत 800 रुपए से अधिक की कीमत वाला सिलेंडर और एक स्टोव मुफ्त में देने की उम्मीद है।

इस साल के बजट में योजना की मंशा की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2021-22 में 1 करोड़ नए लाभार्थियों के लिए योजना का विस्तार करने की घोषणा की थी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, उज्ज्वला योजना, जिसने 8 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया है, को 1 करोड़ से अधिक और लाभार्थियों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा।

फ्री फर्स्ट रिफिल और स्टोव के साथ डिपॉजिट फ्री गैस कनेक्शन के अलावा इस योजना के नए रूप में ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान होगा। अधिकारी ने बताया कि एक प्रवासी परिवार को अलग गैस कनेक्शन भी मिल सकता है। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए 222 भारत में घटिया कानून बनाए

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और पीआईएल मैन के नाम से प्रसिद्ध अश्विनी उपाध्याय ने आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर जंतर मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 1860 में बने इंडियन पीनल कोड, 1861 में बने पुलिस ऐक्ट, 1863 में बने रिलिजियस एंडोमेंट ऐक्ट और 1872 में बने एविडेंस एक्ट सहित सभी 222 अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की मांग की। इसके अलावा भारत में समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान कर संहिता, समान दंड संहिता, समान श्रम संहिता, समान पुलिस संहिता, समान न्यायिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान धर्मस्थल संहिता और समान जनसंख्या संहिता लागू करने की मांग की। भारत जोड़ो अभियान के संयोजक अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि जब तक घटिया 222 अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे तब तक जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, माओवाद, नक्सलवाद, तुष्टीकरण और राजनीति का अपराधीकरण कम नहीं होगा। जब तक घटिया 222 अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे तब तक चोरी लूट झपटमारी घूसखोरी जमाखोरी मिलावटखोरी कालाबाजारी कमीशनखोरी मुनाफाखोरी मानव तस्करी नशा तस्करी चंदन तस्करी हवाला कारोबार कालाधन और बेनामी संपत्ति कम नहीं होगी। जब तक घटिया अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होगा तब तक रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ और साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण समाप्त नहीं होगा।

देश भर से हजारों की संख्या में आये लोगों को संबोधित करते हुए उपाध्याय ने कहा कि अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार और अपराध कम करने तथा भारत के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बल्कि अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए घटिया कानून बनाया था। अंग्रेजों ने कानून बनाते समय किसी भारतीय से विचार विमर्श नहीं किया था। न तो घटिया कानूनों को बनाते समय कोई सार्वजनिक बहस हुई थी और न तो आम जनता से कोई सुझाव लिया गया था। अंग्रेजों ने सभी कानून केवल अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाया था। 1860 का आईपीसी भारत में अपराध कम करने के लिए नहीं बल्कि तिलक और लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटने, वीर सावरकर जैसे देशभक्तों को आजीवन कारावास देने तथा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी देने के लिए बनाया था। उपाध्याय ने कहा कि 1861 का पुलिस ऐक्ट महा घटिया है। इस घटिया कानून के कारण पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलामी थी और अब सत्ताधारी पार्टी की गुलाम है। 1990 में कश्मीर में दिनदहाड़े हत्या हुई थी, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था, खुलेआम घर जलाया गया था और पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन पुलिस ने हवाई फायरिंग भी नहीं की। आज तक कश्मीर के गुनाहगारों को सजा भी नहीं हुई। 1990 में कश्मीर के महा नरसंहार का मूल कारण 1861 में बना घटिया पुलिस ऐक्ट है। जो कुछ 1990 में कश्मीर में हुआ था वह सब कुछ दिन पूर्व बंगाल में भी हुआ लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही क्योंकि 1861 में बना पुलिस ऐक्ट बंगाल में भी लागू है।

30 जवानों ने अफगानिस्तान जाने की लगाई गुहार, हाईकोर्ट से याचिका खारिज

नई दिल्ली। अफगानिस्तान में तालिबान का हमला लगातार जारी है। वहां के नागरिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में किसी अन्य देश से लोग वहां जाने से परहेज कर रहे हैं लेकिन इस बीच एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के कुछ जवानों की ओर से अफगानिस्तान में दोबारा से तैनाती के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटीबीपी के 30 जवानों को झटका देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें आश्चर्य हो रहा कि कोई भी वहां इस खतरनाक और संकट भरी स्थिति में वापस जाने का इच्छुक होगा। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता, आईटीबीपी जैसे सशस्त्र बलों के कर्मियों के रूप में आवश्यकता के आधार पर भारत में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं। हालांकि उनके पास अफगानिस्तान में तैनात होने का कोई निहित अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि याचिकाकताओं को अगस्त 2020 में अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास में सुरक्षा सहायक के रूप में तैनात किया था और उनका कार्यकाल दो साल की अवधि के लिए होना था। हालांकि हमले बढ़ने के बाद 13 जून 2021 को उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। याचिकाकताओं ने दावा किया कि वे अफगानिस्तान में 2 साल के प्रवास के हकदार थे, लेकिन दस महीने की अवधि के लिए सेवा देने के बाद ही उन्हें समय से पहले भारत में फिर से तैनात किया है।

सार समाचार

सऊदी विदेश मंत्री ने यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के नए विशेष दूत की नियुक्ति का स्वागत कियो

याद । सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहान अल सऊद ने यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के शेष दूत हंस ग्रंडबर्ग की नियुक्ति का स्वागत किया । शनिवार को ट्विटर पर मंत्री ने कहा, मैं यमन के ए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में हंस ग्रंडबर्ग ी नियुक्ति का स्वागत करता हूं। हम उनकी नई मिका में उनकी सफलता की कामना करते हैं और नके साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। राज्य एक जनीतिक समाधान तक पहुंचने के सभी प्रयासों का मर्थन करना जारी रखेगा जो यमन में शांति और मृद्धि लाने में मदद करता है। समाचार एजेंसी की पोर्ट के अनुसार, ग्रंडबर्ग ने मार्टिन ग्रिफिथ्स का थान लिया है, जिन्हें मानवीय मामलों के लिए संयुक्त ष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया । मार्च में, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने मन में यमनी सरकार के समर्थन में हौथी मिलिशिया खिलाफ युद्ध का अपना छठा वर्ष पूरा किया। 22 ार्च को, सऊदी अरब ने यमनी संकट को समाप्त रने के लिए एक पहल की घोषणा की। इस पहल में युक्त राष्ट्र की देखरेख में यमन में व्यापक संघर्ष राम शामिल है। यह उन पहलों की एक श्रृंखला का स्सा था जिन्हें मिलिशिया ने वर्षों से खारिज कर या था।

आयरलैंड में जोरदार टीका कंपेन के बावजूद तेजी से नए कोविड मामले सामने आए

बलिन। उच्च टीकाकरण दर प्राप्त करने के बावजूद, ायरलैंड के दैनिक कोविड -19आंकड़ो ने संक्रमण ी वर्तमान लहर के टूटने के बाद से एक और रिकॉर्ड नाया है। समाचार एजेंसी ने स्वास्थ्य विभाग के वाले से बताया कि शनिवार को आयरलैंड में कोरोना 1,828 नए पुष्ट मामले सामने आए। विभाग के ांकड़ों के अनुसार, यह लगातार दूसरा दिन है जब ायरलैंड ने मौजूदा लहर में रिकॉर्ड उच्च मामलों की ूचना दी। स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्सा धिकारी रोनन ग्लिन ने कहा कि आयरलैंड में 14-वसीय घटना दर बढ़कर 386 प्रति 100,000 नसंख्या हो गई है, जो कि फरवरी की शुरूआत से बसे अधिक है। आयरलैंड में दैनिक मामलों की ंख्या जुलाई के मध्य में पांच महीने से अधिक समय पहली बार 1,000 के स्तर को पार करने के बाद, गातार 22 दिनों तक उस आंकड़े से ऊपर रहा है। 6 जुलाई को समाप्त सप्ताह में, आयरलैंड ने 9,000 अधिक पुष्ट मामलों की सूचना दी, जो संक्रमण की हली और दूसरी लहर में दर्ज उच्चतम साप्ताहिक ंख्या से कहीं अधिक है, जो पिछले साल अप्रैल और क्टूबर में देश में आई थी। आयरलैंड में कोरोना ामलों में तेजी ऐसे समय में आई है जब देश ने ोविड -19 के खिलाफ आबादी का टीकाकरण रने में उल्लेखनीय प्रगति की है। कोविड19 पर बिनेट कमेटी ने कहा कि आयरलैंड में सभी आयु मूहों में (कोविड -19 वैक्सीन का) स्तर ंतरराष्ट्रीय तुलना से अधिक है।

इजराइल के साथ किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार : हिज्बुल्लाह

रुत। हिजबुल्लाह नेता सैय्यद हसन नसरल्लाह ने कहा कि लेबनानी शिया आंदोलन किसी इजरायली युद्ध नहीं डरता और वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है। माचार एजेंसी सिन्हुआ ने नसरल्लाह के हवाले से हा, हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमें कीन है कि हम इसे जीतेंगे। पिछले दो दिनों में बनान और इजराइल के बीच रॉकेट के आदान-दान के बाद नसरल्लाह की टिप्पणी आई है। जबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में गुरुवार को इजरायल हवाई हमले के जवाब में कब्जे वाले शेबा फार्म में जरायल के ठिकानों के खिलाफ शुक्रवार को रॉकेट गे।

यमन के मारिबो में 45 हौथी विद्रोही मारे गए

ना। पिछले 24 घंटों में तेल समृद्ध प्रांत मारिब में यमनी रकार की सेना के साथ जमीनी संघर्ष में, सऊदी के तृत्व वाले गठबंधन द्वारा कई हवाई हमलों में कम से म 45 हौथी विद्रोही मारे गए। सैन्य सूत्रों ने इस खबर ी पुष्टि की है। मारिब के एक सूत्र ने शनिवार को माचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि पश्चिमी जिले रवाह में, हवाई हमले में एक विद्रोही अस्थायी चालन कक्ष को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से म 12 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि सिरवाह के क्षिण में स्थित राहाबा जिले में, हवाई हमले में विद्रोही ड़ाकों को ले जा रहे कई पिकअप वाहन नष्ट हो गए, जसमें 20 से अधिक लोग मारे गए। एक अन्य सैन्य त्र ने कहा कि सेना ने राहाबा जिले में अल-बयाद और ल-अबजख के पहाड़ों में अपनी स्थिति पर तीन शाओं से हूती विद्रोहियों द्वारा शुरू किए गए एक षण हमले को विफल कर दिया। उन्होंने सिन्हुआ को ताया कि 13 विद्रोही जमीन पर मारे गए, जबकि दर्जनों ाग गए। दोनों रणनीतिक पहाड़ों और राहाबा जिले के धिकांश हिस्सों पर पिछले हफ्ते सेना ने कब्जा कर या था।

महामारी के बीच 10 लाख से ज्यादा अमेरिकी बच्चों ने स्कूलों में नहीं लिया दाखिला

शिंगटन। अमेरिका में 10 लाख से अधिक बच्चों ने कूलों में दाखिला नहीं लिया है। इसमें किंडरगार्टन में बसे तेज गिरावट के साथ 340,000 से ज्यादा छात्र , क्योंकि देश में कोविड-19 महामारी का कहर ारी है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। माचार एजेंसी सिन्हुआ ने शनिवार को प्रकाशित द ू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि जिन च्चों के स्थानीय स्कूलों में दाखिला लेने की उम्मीद ी, वे या तो व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन नहीं ाए, और लापता छात्र छोटी कक्षाओं में केंद्रित थे। मांकन के विश्लेषण के अनुसार 70,000 33 मेरिकी राज्यों में पब्लिक स्कूल रिपोर्ट में कहा गया कि स्वास्थ्य देखभाल और आय में भारी समानताओं को ट्रिगर करने के अलावा, महामारी ने क्षा में असमानताओं को कठोर कर दिया, कुछ बसे कमजोर छात्रों को कक्षा में एक दिन भी बिताने

अमेरिका में फिर पैर पसारने लगा कोरोना, संक्रमण के औसतन एक लाख नए मामले दर्ज

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिका में शनिवार को कोविड-19 के एक लाख से अधिक नए मामले सामने आए। इससे पहले, सर्दियों में इतने अधिक मामले आए थे। इन मामलों के पीछे वजह वायरस का बेहद संक्रामक डेल्टा स्वरूप है और एक अन्य कारण दक्षिण में टीकाकरण दर कम होना है। स्वास्थ्य अधिकारियों को डर है कि यदि और अमेरिकी टीका नहीं लगवाएंगे तो मामले, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो सकती है। देश में 50 फीसदी लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है और 70 प्रतिशत से अधिक वयस्क आबादी को कम से कम एक टीका लग चुका है।

रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के निदेशक रोशेल वालेन्स्की ने इस हफ्ते सीएनएन से कहा, ''हमारे मॉडल दिखाते हैं कि अगर हम लोगों को टीके नहीं लगाते हैं तो एक दिन में हजारों मामले सामने आ सकते हैं जो जनवरी में संक्रमण के चरम पर पहुंचने के समय रहे मामलों के बराबर हो सकते हैं।'' देश में जून के अंत से ही हर दिन औसतन 11,000 मामले सामने आ रहे है। अब यह संख्या 1,07,143 हो गई है। अमेरिका में नौ महीने के अंतराल के बाद नवंबर में दैनिक औसत मामलों का आंकड़ा 1,00,000 पहुंच गया था। जनवरी की शुरुआत तक रोजाना के मामले करीब 2,50,000 पर पहुंच गए थे।

अस्पताल में भर्ती मरीजों की और मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, हालांकि जनवरी के मुकाबले ये दोनों आंकड़े अभी कम हैं लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तब टीके इतने व्यापक तरीके से उपलब्ध नहीं थे। अभी कोविड-19 से पीड़ित 44,000 से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और सीडीसी के मुताबिक इनमें एक हफ्ते में 30 फीसदी की वृद्धि हुई है और जून के मुकाबले ये आंकड़े चार गुना बढ़ गए हैं। जनवरी में 1,20,000 से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती थे। जॉन हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के मुताबिक सात दिन के औसत के हिसाब से शुक्रवार को एक दिन के भीतर औसतन करीब 500 लोगों की मौत हुई। दो सप्ताह पहले यह आंकड़ा करीब 270 मृत्यु का था। जनवरी में यह आंकड़ा प्रतिदिन 3,500 था।

दक्षिण हिस्से में स्थिति खासतौर पर बिगड़ी हुई है जहां टीकाकरण दर सबसे कम हैं। सीडीसी के मुताबिक दक्षिण पूर्व क्षेत्र में

अस्पताल में भर्ती कोविड-19 मरीजों की संख्या पिछले सप्ताह के मुकाबले 50 प्रतिशत बढ़ गई है। पिछले सप्ताह जहां रोजाना औसतन 11,600 मरीज इलाज करा रहे थे अब यह संख्या 17,600 हो गई है।

कैलिफोर्निया में लगी भयावह 'डिक्सी' आग, डर के साये में जी रहे निवासी

ग्रीनविले। (एजेंसी)।

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी भयावह 'डिक्सी' आग के कारण ग्रीनविले शहर के निवासियों के मन में भय है, जहां हजारों घरों के जलकर राख हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। तेज हवाओं और बेहद शुष्क वनस्पति के कारण भड़की आग राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी आग का रूप लेने जा रही है। चार साल से बेघर रही केसिया स्टडबेकर बमुश्किल अपने हालातों से उबर पाईं थी कि इस आग में फिर से सबकुछ बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया है।

स्टडबेकर ने कहा, 'हमें पता था कि पर्याप्त बारिश नहीं हुई है और आग लग सकती है लेकिन हमने इस तरह की भयावहता की कल्पना नहीं की थी।' बुधवार और बृहस्पतिवार को इस आग ने ग्रीनविले के अधिकांश हिस्से को जला दिया था। इसने 370 घरों और ढांचों को अपनी जद में ले लिया और उत्तरी सियेरा नेवादा में करीब 14,000 इमारतों पर इसकी चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। न्यूयॉर्क सिटी के आकार से बड़ा हिस्सा इसकी जद में आ चुका है।

कैलिफोर्निया के वन एवं अग्नि सुरक्षा विभाग के मुताबिक 'डिक्सी फायर' शनिवार रात 1,813 वर्ग किलोमीटर तक के इलाके में फैल चुकी है और इसपर अबतक महज 21 प्रतिशत तक काबू पाया जा सका है। पेड़ की शाखा टूटकर गिरने के बाद शुक्रवार को चार दमकलकर्मियों को अस्पताल ले जाना पड़ा। शुरुआत में 20 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर थी लेकिन शनिवार दोपहर को अधिकारियों का पांच लोगों को छोड़कर सभी से संपर्क हो गया था। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पैसेफिक गैस एवं बिजली केंद्र ने कहा है कि यह आग संभवत÷ एक पेड़ के उसके बिजली की तारों पर गिर जाने के कारण लगी है।

एक संघीय न्यायाधीश ने केंद्र को उपकरण एवं वनस्पति के ब्योरे देने को कहा है जहां से 16 जुलाई से आग लगी थी। रात में तापमान कम रहने और अधिक नमी होने से आग का प्रसार धीमा हो गया है। लेकिन इस आग और आस-पड़ोस में फैली अन्य आगों के चलते खतरा अभी टला नहीं है। बाकी अन्य आग एक-दूसरे से महज कुछ सैकड़ों मील की दूरी पर ही लगी हैं।

2021 का पहला छह महीना, साल 2009 के बाद से अफगानिस्तान का सबसे खूनखराबा वाला दौर रहा

नई दिल्ली/काबुल (एजेंसी)।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) को एक ब्रीफिंग में अफगानिस्तान स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष शहजाद अकबर ने कहा कि इस साल के पहले छह महीने साल 2009 के बाद से युद्ध के लिए सबसे खूनी रहे हैं। महिलाओं और बच्चों सहित 1,677 नागरिक मारे गए, जबकि 3,644 अन्य घायल हुए। अकबर ने यूएनएससी को बताया, अगर हिंसा की मौजूदा दर जारी रहती है, तो मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि इस साल के अंत तक नागरिक क्षति का एक गंभीर नया रिकॉर्ड हो सकता है। जिलों और अब एक प्रांतीय शहर तालिबान के अधीन होने के साथ, आगे क्या होता है यह देखने के लिए लाखों अफगान आतंक में इंतजार कर रहे हैं।

इस परिषद और इसके सदस्यों के पास अभी भी अफगानों के खून बहने को रोकने और तबाही को रोकने का लाभ है। यह परिषद जीवन बचा सकती है। हमें बचाने के लिए राजनीतिक, राजनयिक, मानवाधिकार और मानवीय उपकरणों और हस्तक्षेपों की पूरी श्रृंखला का उपयोग करने के लिए परिषद की आवश्यकता होगी और आगे और अधिक भयानक अत्याचारों को रोक सकती है। हम परिषद, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्रों से आग्रह करते हैं कि वे नागरिक सुरक्षा, युद्धविराम, हिंसा की समाप्ति और सार्थक और समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया के लिए अफगान कॉलों का अधिक से अधिक तत्परता से जवाब दें।

उन्होंने कहा, महिलाएं विशेष रूप से अपनी आजादी और अपने लोगों के खिलाफ तालिबान के अतीत और वर्तमान की गालियों को याद करती हैं और आने वाले समय से डरती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कई लोग इस बिगड़ते हालात से भागने की कोशिश करने वालों की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। स्पिन बोल्डक, कंधार में, आयोग के निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि लक्षित, गैर-न्यायिक हत्याओं के अभियान में तालिबान ने सरकार से जुड़े कम से कम 40 नागरिकों को खींच लिया और मार डाला। मीडिया और मानवाधिकारों की रिपोर्टिंग के बाद, तालिबान ने सख्त प्रतिबंध लगाए और इन अत्याचारों के पूर्ण दस्तावेज को रोकने के लिए स्पिन बोल्डक से आने-जाने वाले लोगों की जांच करेंगे। मलिस्तान, गजनी प्रांत में, आयोग ने पुष्टि की कि तालिबान द्वारा लक्षित हत्याओं में कम से कम 27 नागरिकों की हत्या कर दी गई थी।

एक उदाहरण में, तालिबान ने नागरिकों के शवों को स्थानांतरित करने के लिए एक निहत्थे गार्ड की मदद मांगी और फिर गवाहों को खत्म करने के प्रयास में गार्ड को मार डाला। हेलमंद में, प्रांतीय राजधानी लश्कर गाह के निवासी तालिबान के हमलों और सरकारी हवाई हमलों के बीच फंस गए हैं, हर मिनट अपने जीवन के लिए डरते हैं और अपने मूल अधिकारों तक पहुंच से वंचित हैं। संघर्ष के कानूनों के उल्लंघन के अलावा, अफगानिस्तान के मानवाधिकार लाभ पर हमला हो रहा है और संघर्ष के विस्तार के रूप में तेजी से सिकुड़ रहा है। अकबर ने परिषद को जानकारी देते हुए कहा कि तालिबान के कब्जे वाले क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का एक प्रमुख, गंभीर उदाहरण है। शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच, बाजारों तक, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित और सिकुड़ती जा रही है। उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित और दमन किया गया है। अफगानिस्तान में अफगान महिलाएं या तो तालिबान क्षेत्र के दुस्वप्न को फिर से जी रही हैं या जल्द ही इसे फिर से जीने के डर और आघात में जी रही हैं। अगर ज्वार नहीं बदलता है और हमारे पास बातचीत और उनमें सार्थक भागीदारी का अवसर नहीं है। उन्होंने कहा, सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ हमारे पास समान रूप से संबंधित स्थिति है। चूंकि मीडिया संघर्ष के लिए दोनों पक्षों के दबाव में है, इसलिए विभिन्न प्रांतों में स्वतंत्र मीडिया बंद हो रहा है क्योंकि तालिबान के अधिक जिलों का पतन हो रहा है।

आतंकवादी समूह हिजबुल्ला लेबनान पर भविष्य में इजराइल के किसी भी हवाई हमले का देगा जवाब

बेरूत। (एजेंसी)।

आतंकवादी समूह हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्लाह ने शनिवार को कहा कि उसका समूह लेबनान पर भविष्य में इजराइल के किसी भी हवाई हमले का जवाब देगा। इससे एक दिन पहले हिजबुल्ला ने इजराइल की ओर कई रॉकेट दागे थे। नसरल्लाह ने कहा कि यह मान लेना गलत होगा कि हिजबुल्ला लेबनान में आंतरिक मतभेदों या देश के खराब आर्थिक हालात के कारण रुकेगा। नसरल्ला की यह टिप्पणियां तब आयी है जब एक दिन पहले उसके समूह ने इजराइल की ओर रॉकेट दागते हुए इसे दक्षिण लेबनान पर इजराइली हवाई हमलों का जवाब बताया। लेबनान की सीमा पर लगातार तीन दिन से हमले हो रहे हैं। लेबनान की सीमा पश्चिम एशिया में संघर्ष का एक प्रमुख स्थान है, जहां इजराइल और ईरान के बीच तनाव रहता है। ईरान हिजबुल्ला का समर्थन करता है।

नसरल्ला ने 2006 के इजराइल-हिजबुल्ला युद्ध को खत्म होने की 15वीं वर्षगांठ पर टेलीविजन पर दिए भाषण में कहा, ''लेबनान पर इजराइली वायु सेना के किसी भी हवाई हमले का उचित तरीके से जवाब दिया जाएगा क्योंकि हम अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। यह कहकर गलत आकलन न करें कि हिजबुल्ला लेबनान की समस्याओं में व्यस्त है।'' हिजबुल्ला के नेता ने कहा कि रॉकेट दागना एक ''स्पष्ट संदेश'' था। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला ने खुले मैदान में 20 रॉकेट दागे क्योंकि इजराइल ने भी खुले मैदान में बृहस्पतिवार को हवाई हमले किए थे।

गौरतलब है कि लेबनान अपने आधुनिक इतिहास में अब तक के सबसे खराब आर्थिक और वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इजराइल ने अनुमान जताया कि हिजबुल्ला के पास 130,000 से अधिक रॉकेट और मिसाइल हैं तथा वह देश में कहीं भी हमले करने में समर्थ है। नसरल्ला ने कहा, ''हम हमेशा कहते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं।'' हिजबुल्ला नेता ने अपने भाषण में उस न्यायाधीश की कड़ी आलोचना की जिसने बेरूत के एक बंदरगाह में पिछले साल हुए विस्फोट की जांच की थी जिसमें कई लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। नसरल्ला ने कहा कि न्यायाधीश तारिक बितर का काम ''राजनीति'' से प्रेरित है।

पोम्पिओ को दी गई 5800 डॉलर की व्हिस्की कहां गई? पता लगा रहा है विदेश विभाग

वाशिंगटन (एजेंसी)।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ को तोहफे में मिली 5,800 अमेरिकी डॉलर की जापानी व्हिस्की का पता नहीं चलने से अमेरिकी विदेश मंत्रालय हैरान है और इस महंगी शराब का क्या हुआ यह पता लगाने की लिए जांच शुरू की गई है। सीएनएन ने एक संघीय रजिस्टर में विदेश विभाग की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग बोतल का पता लगा रहा है। दस्तावेजों में कहा गया कि जापान सरकार ने पोम्पिओ को 2019 में यह व्हिस्की तोहफे में दी थी। विभाग ने यह पता लगने पर असामान्य कदम उठाया कि व्हिस्की की बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक बीते दो दशकों में ऐसी जांचों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। विदेश मंत्रालय की टिप्पणी के मुताबिक, 'विभाग इस मामले को देख रहा है और एक जांच चल रही है।' यह हालांकि स्पष्ट नहीं है कि पोम्पिओ ने खुद यह

व्हिस्की प्राप्त की थी या किसी कर्मी ने इसे स्वीकार किया था। पोम्पिओ ने कहा कि उन्होंने कभी व्हिस्की की कोई बोतल प्राप्त नही की और उन्हें इसकी 'कोई जानकारी नहीं' की यह गायब है, न ही यह पता है कि तोह्फे का क्या हुआ। फॉक्स न्यूज पर पेश हुए पूर्व विदेश मंत्री ने कहा, 'मुझे लगता है कि इसे कभी छुआ नहीं गया था। यह कभी मुझतक नहीं पहुंची। मुझे कोई जानकारी नहीं है कि विदेश विभाग ने यह चीजें कैसे खो दीं, यद्यपि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने विदेश विभाग में काफी अक्षमताएं देखी थीं।' उन्होंने कहा, 'अगर वह डाइट कोक की पेटी होती तो उसे पूरा गटक जाता।'

ब्रिटेन ने भारत का नाम लाल सूची से हटाकर यात्रा प्रतिबंधों में दी ढील, अब वैक्सीन ले चुके यात्रियों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य नहीं !

लंदन। (एजेंसी)।

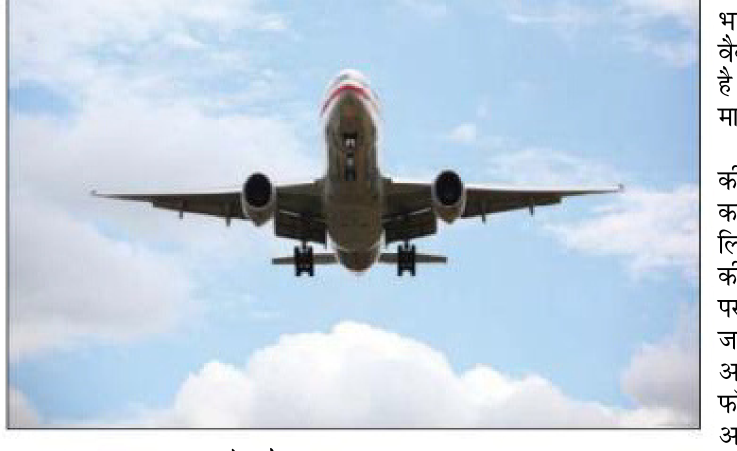

ब्रिटेन ने रविवार को भारत का नाम ÷लाल÷ सूची से हटाकर 'ऐंबर÷ सूची में डालने के साथ ही देश के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी। इसका मतलब यह हुआ कि कोविड-19 टीके की सभी खुराकें ले चुके भारतीय यात्रियों के लिए अब ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिन तक होटल में पृथक-वास में रहना अनिवार्य नहीं होगा। स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल विभाग (डीएचएससी) ने पुष्टि की कि रविवार सुबह चार बजे तक ऐंबर सूची में रखे गए देश, भारत से आने वाले सभी लोग जिन्हें भारत में टीका लग चुका है, उन्हें अपने घरों पर या भौगोलिक स्थिति दर्शाने वाले अनिवार्य फॉर्म में उल्लेखित निर्दिष्ट स्थान पर एकांतवास में रहना होगा। सरकार अनुमोदित पृथक-वास केंद्र में प्रति व्यक्ति 1,750 पाउंड के अतिरिक्त खर्च पर अनिवार्य रूप से 10 दिन रहने की शर्त अब लागू नहीं होगी लेकिन घर में पृथक-वास में रहने से छूट केवल उन लोगों को होगी जिन्हें ब्रिटेन या यूरोप में टीका लगा है।

लगाए जा रहे हैं और यह निर्धारित करने का काम जारी है कि किस गैर-ब्रितानी टीके एवं प्रमाणन समाधान को मान्यता देनी है।÷ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड/ एस्ट्राजेनेका के टीके 'कोविशील्ड' को ब्रिटेन स्वीकृत टीकों के व्यापक दायरे में शामिल किए जाने को लेकर कुछ अकटलें हैं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्रिटेन

ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के भारत-निर्मित संस्करण को वैक्सजेवरिया ब्रांड का नाम दिया गया है और वर्तमान में छूट नियमों के तहत मान्यता प्राप्त यही एकमात्र टीका है।

ब्रिटेन की यातायात रोशनी प्रणाली की ऐंबर सूची में मौजूद देशों के लिए कानूनी नियमों के तहत, यात्रियों के लिए प्रस्थान से तीन दिन पहले कोविड की जांच कराना और ब्रिटेन पहुंचने पर जांच कराने के लिए दो कोविड जांचें पहले से बुक करने के साथ ही आगमन पर यात्री भौगोलिक स्थिति फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। इंग्लैंड में आगमन पर, यात्रियों को घरों में या जिस स्थान का उन्होंने फॉर्म में उल्लेख किया है वहां 10 दिन पृथक-वास में रहना होगा और उन्हें दूसरे दिन या उससे पहले कोविड-19 की एक जांच और आठवें दिन या उसके बाद एक जांच करानी होगी। सभी नियमित निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। हालांकि, ब्रिटेन और भारत सरकार के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत, भारत और ब्रिटेन के बीच

अपने गठन के 54 साल बाद, शांति, विकास सुनिश्चित करने में आसियान सफल

नोम पेन्ह (एजेंसी)।

कम्बोडियन प्रधानमंत्री हुन सेन ने रविवार को आसियान दिवस को चिह्नित करने के लिए एक संदेश में कहा, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) शांति, स्थिरता, सुरक्षा और स्थिर विकास सुनिश्चित करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि एक साथ मिलकर, हमने इस क्षेत्रीय संगठन के विकास को एक एक लंबी और पूर्ण यात्रा शुरू की है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, आसियान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। सेन ने कहा कि आसियान हमेशा कंबोडिया की विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है। आसियान ढांचे के माध्यम से, हम सभी क्षेत्रों में टिकाऊ शांति, सुरक्षा, समृद्धि और राष्ट्रीय विकास को बनाए रखने के लिए क्षेत्र के देशों और दुनिया भर के बाहरी भागीदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को बढ़ाने के अवसरों को अधिकतम करने में सक्षम हैं। एक क्षेत्रीय समूह के रूप में, आसियान अब तक यह सुनिश्चित करने में सफल रहा है कि उसके

दिल्ली में बेघर गरीबों को अब सभी रैन बसेरों में मिलेगा खाना

- केजरीवाल सरकार ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू की मुख्यमंत्री पोषाहार योजना
- फाउंडेशन शहर में हर दिन 209 रैन बसेरों के लिए 10,000 मील्स मुहैया कराएगा

रैन बसेरों में रहने वाले लोग किसी भी पार्टी के वोट बैंक नहीं होते हैं। इसलिए आज तक देश भर में सरकारों ने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार बनने से पहले तक दिल्ली हाईकोर्ट से हर साल दिल्ली सरकार रैन बसेरों में बदइंतजामी पर डांट खाती थी। आज हमारी सरकार ने रैन बसेरों की हालत बहुत अच्छी कर दी है :- अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

नई दिल्ली, 8 अगस्त **,एजेंसी।** दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सराय काले खां स्थित दिल्ली अर्बन स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड डीयूएसआईबी शेल्टर कॉम्प्लेक्स में आयोजित इवेंट में शहर के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की नाइट शेल्टर फीडिंग पहल का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत, फाउंडेशन डीयूएसआईबी द्वारा संचालित 209 रैन बसेरों में लंच और डिनर मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। 5,000 से ज्यादा बेघर लोगों को इस पहल का लाभ मिलेगा, जिनमें परिवार बुजुर्ग व्यक्ति, विधुर, विधवा महिलाएं, बुरी लत से जूझ रहे लोग, चिकित्सा के अभाव वाले लोग शामिल होंगे। यह आंकड़ा जाड़े के मौसम में दोगुना हो जाने की संभावना है, क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग पूरे शहर में रैन बसेरों की मदद लेते हैं। इस इवेंट के लिए मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। सम्मानित अतिथि के तौर पर शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय पात्र फाउंडेशन के चेयरमैन मधु पंडित दासा और वाइस-चेयरमैन चंचलपति दासा द्वारा की गई थी। इस अवसर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वोट नहीं बने होने के कारण रैन बसेरों में रहने वाले लोग किसी भी पार्टी के वोट बैंक नहीं होते हैं। इसलिए आज तक देश भर में सरकारों ने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार बनने से पहले तक दिल्ली हाईकोर्ट से हर साल दिल्ली सरकार रैन बसेरों में बदइंतजामी पर डांट खाती थी। आज हमारी सरकार ने रैन बसेरों की हालत बहुत अच्छी कर दी है और अब लोग कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए कुछ किया तो है। सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार है। हमने सबसे ज्यादा काम गरीबों के लिए किया है। दिल्ली सरकार और अक्षय पात्रा फाउंडेशन की साझेदारी से अब सभी रैन बसेरों में हमेशा खाना खिलाया जाएगा। लॉन्च इवेंट के बाद शेल्टर परिसर में भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मौजूद लोगों ने कोविड-19 महामारी के दौरान भूख और कुपोषण की समस्या दूर करने के अक्षय पात्र के प्रयासों की सराहना की, और फाउंडेशन के कार्यों को अपना समर्थन देने की इच्छा प्रकट की।

चंचलपति दासा ने कहा, 'हम आज शुरू की गई नाइट शेल्टर फीडिंग पहल के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के आभारी हैं। उनके सक्षम नेतृत्व में, दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए शानदार कार्य कर रही है कि समाज के कमजोर वर्ग की बुनियादी जरूरतों को इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा किया जाए। नाइट शेल्टर फीडिंग पहल के लिए अपना समर्थन देने के लिए मैं सत्येंद्र जैन जी और डीयूएसआईबी का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। यह पहल हमें शहर में हजारों बेघर लोगों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी।' उन्होंने कहा, 'हमने इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों की मदद से पिछले मार्च से दिल्ली एनसीआर में लोगों को 1 करोड़ से ज्यादा मील्स प्रदान किए हैं।

दक्षिणी निगम ने बड्डी कंपोस्टरों को किया सम्मानित

नई दिल्ली, 8 अगस्त **(एजेंसी)।** दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने कूड़े के पृथक्करण एवं अपनी बड्डी कंपोस्टर मुहिम की सफलता को मनाने एवं इससे जुड़े नागरिकों को सम्मानित करने के लिए वसंत कुंज स्थित होटल ग्रांड में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर गीले कूड़े के निस्तारण एवम होम कम्पोस्टिंग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को क्षेत्रीय उपायुक्त डा सोनल स्वरूप ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा इसके साथ ही बड्डी कंपोस्टर मुहिम से जुड़े क्षेत्र के नागरिकों ने अपने अनुभव, इसके फायदे एवं घर पर कम्पोस्टिंग करते समय आने वाली चुनौतियों से संबंधित संस्मरण साझा किए। । इस अवसर पर वेस्ट चैंपियंस, जी.के.-2 के जयादित्य एवं रश्मि खुराना ने अपनी कूड़ा प्रबंधन कौशल साझा किए जिसके अंतर्गत जयादित्य ने रसोई में बचे बीजों को खाद में मिलाकर तथा रश्मि खुराना ने कागज की कतरनों, सूखे पत्तों एवं फूल की पत्तियों से बनी कलाकृति

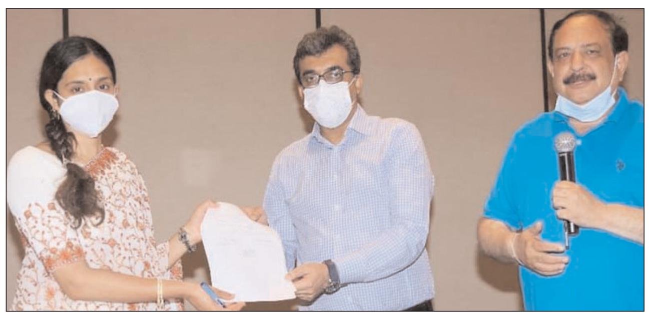

प्रदर्शित की। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र की उपायुक्त डॉ सोनल स्वरूप ने पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग के अभियंताओं के साथ मई 2021 में बड्डी कंपोस्टर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। डा सोनल स्वरूप ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत घरों से निकलने वाले गीले कूड़े का स्त्रोत पर ही प्रबंधन करके उससे जैविक खाद उत्पन्न की जा रही है तथा यह कार्यक्रम समाज के अंदर बेहतर सामंजस्य एवं मित्रता की भावना पर आधारित है। इस कार्यक्रम को नागरिकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली तथा वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्र के लगभग 500 घर बड्डी कंपोस्टर की मुहिम से जुड़ गए हैं जिनमे से 282 घर पिछले 2 माह में जुड़े हैं।

इसी कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान के बारे में भी चर्चा की गई तथा क्षेत्र के प्रमुख अस्पताल जैसे, मैक्स साकेत, फोर्टिस, लाफेम फोर्टिस जी के 2, पी एस आर आई, सीताराम भरतिया, आइस क्रीम पार्लर जैसे ज्ञानी, बास्किन रोबिन, नैचुरल, मोटेल जैसे बैलमंड, ओसियन रिट्रीट, इत्यादि के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया जिसके अंतर्गत सभी संस्थान अपने परिसरों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करेंगे तथा अपने आस पड़ोस में सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में नागरिकों को जागरूक करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाल में हुए विस्तार के बाद बनाये नए मंत्रियों के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में जन आशिर्वाद यात्रा निकालेगी। प्रदेश भाजपा ने भी इस यात्रा के लिए तैयारियां शुरु कर ली है और दिल्ली से इस यात्रा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी शामिल होंगी। प्रदेश भाजपा महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जो कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, ने बताया कि प्रदेश में 14 जिले हैं और दोनों मंत्री 7-7 जिलों में यात्रा निकालेंगे। हर्ष मल्होत्रा के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा भी रहेंगे। उन्होंने बताया कि तीन दिन की यह यात्रा 16 अगस्त से शुरु होगी और इसका समापन 18 अगस्त को होगा। यात्रा के दौरान और दिन के अंत में यात्रा के समापन पर एक जनसभा आयोजित की जाएगी जिसमें भाजपा की केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जनता को दी जाएगी। मल्होत्रा ने बताया कि श्री हरदीप सिंह पुरी अपनी यात्रा पश्चिमी दिल्ली जिले से शुरु करेंगे जबकि श्रीमती मीनाक्षी लेखी अपनी यात्रा अपने संसदीय क्षेत्र के करोल बाग़ जिले से शुरु करेंगी।

क्राइम पेट्रोल देखकर खिलौने की पिस्तौल से डालते थे डकैती, दो गिरफ्तार

दिल्ली। मैदानगढ़ी थाना पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में हुई कई डकैती के मामलों को दो बदमाशों के गिरफ्तार करने के बाद सुलझा दिया है। आरोपी खिलौने की पिस्तौल से कैश फॉर गोल्ड के मामले में डीलिंग करने वाले शोरुम को निशाना बनाते थे। डकैती की प्लानिंग आरोपी क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर बनाते थे। आरोपियों 24 वर्षीय धीरज और 27 वर्षीय पंकज के पास से 4 हजार रुपए, एक स्कूटी, दो खिलौने की पिस्तौल, वारदात के दौरान पहनने वाले रैन कोर्ट, ग्लब्स, हेलमेट और मास्क बरामद किए है। आरोपियों पर आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। आरोपी लूट से मिले पैसे को ऑनलाइन गैम्बलिंग में लगाया करता थे। पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि 30 जुलाई को ग्रेटर कैलाश स्थित कैश फॉर गोल्ड की ब्रांच की सर्विस मैनेजर सोनाक्षी सिन्हा ने पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि दो लोग उनकी ब्रांच में आए और पिस्तौल दिखाकर ब्रांच में मौजूद 75 हजार रुपए कैश लूट कर ले गए। सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि दोनों बदमाश स्कूटी से रिंग रोड की तरफ भागे थे। पुलिस ने उनकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की।

दिल्ली में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के महज 66 नये मामले सामने आये तथा अच्छी खबर यह है कि इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,36,761 हो गई है तथा मृतकों का आंकड़ा 25,066 पर ही स्थिर बना रहा। इस दौरान 95 और लोगों के स्वस्थ होने से संक्रमण को मात देने वालों की संख्या 14,11,159 हो गई है। इसी अवधि में 29 सक्रिय मामलों में गिरावट के साथ इनकी संख्या घट कर 536 हो गई है। दिल्ली में कोरोना सकारात्मकता दर 0.10 फीसदी है जबकि मृत्यु दर 1.74 प्रतिशत है।

क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए दस्तावेज लेकर उस पर फाइनेंस करा ली बाइक

पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की

नई दिल्ली, 8 अगस्त **(एजेंसी)।** साइबर ठगों ने ठगी का नया तरिका ढूंढ लिया है। आरोपी लोगों को फोन कर उसने क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर उनके दस्तावेज ले रहे हैं और फिर उन पर लोन लेकर फरार हो जा रहे हैं। नजफगढ़ के धर्मपुरा इलाके में ऐसा मामला सामने आया है। पीड़ित साफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी शिकायत पर नजफगढ़ थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आरोपियों ने पीड़ित के दस्तावेज पर ढ़ाई लाख रुपए की बाइक ली थी और उसकी किस्त नहीं भरी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित नितिन पहल अपने परिवार के साथ धर्मपुरा नजफगढ़ रहता है और बड़ी कम्पनी में साफ्टवेयर इंजीनियर है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में नितिन ने बताया कि 8 जुलाई को उसके पास एक फोन आया और फोन करने वाले ने खुद को एसबीआई बैंक का प्रतिनिधी बताया। उसने कहा कि बैंक नितिन को अच्छे आफर दे रहा है और वह क्रेडिट कार्ड बनवा ले। नितिन उसके झांसे में आ गए और उसने अपने सारे दस्तावेज उसे कार्ड बनवाने के लिए दे दिया। कुछ देर बाद फोन करने वाले दोबारा फोन किया और बताया कि आप का कार्ड बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है। जिसके बाद आरोपी ने उसकी पत्नी के नाम पर कार्ड बनवाने के लिए उनके भी दस्तावेज ले लिया और फोन काट दिया। जिसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया।

साप्ताहिक बाजारों को भी प्राइवेट माफिया को देने की तैयारी में भाजपा की एमसीडी: दुर्गेश पाठक

नई दिल्ली, 8 अगस्त **(एजेंसी)।** आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा की एमसीडी साप्ताहिक बाज़ारों को भी प्राइवेट माफिया को देने की तैयारी में है। प्राइवेट हाथों में जाने से हज़ारों गरीब लोगों का रोज़गार छिन जाएगा। प्राइवेट माफिया अपने लोगों की ही दुकानें लगवाएगी जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट माफिया के माध्यम से मोटा पैसा खाने में जुटी दिल्ली भाजपा। उन्होंने कहा, आगामी स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। यदि यह प्रस्ताव पास होता है तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर भी उतरकर प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने रविवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

प्राइवेट हाथों में जाने से हज़ारों गरीब लोगों का रोज़गार छिन जाएगा। प्राइवेट माफिया अपने लोगों की ही दुकानें लगवाएगी जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा:- दुर्गेश पाठक, वरिष्ठ नेता व एमसीडी प्रभारी

दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिलली के अंदर जो सबसे गरीब तपका है, जो अपना रोजगार वीकली मार्केट में रेहड़ी लगाकर निकालता और अपना जीवन यापन करता है, उसके लिए यह पूरा कोरोना काल बहुत दुखमय रहा है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने इस तपके को सुविधा देते हुए कल से यानी कि सोमवार से सभी वीकली मार्केट खोलने का आदेश दिया है। यानी कि कल से दिल्ली में सभी वीकली मार्केट खोली जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक खतरनाक प्रस्ताव लेकर आ रही है। अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो दिल्ली का जो सबसे गरीब तपका है, भारतीय जनता पार्टी उसका भी खून बहुत ही संगठित तरीके से चूसने का काम शुरू करेगी।

आम आदमी पार्टी साप्ताहिक बाजारों के संबंध में फैला रही है झूठः जोगी राम जैन

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति अध्यक्ष जोगी राम जैन ने आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर साप्ताहिक बाज़ारों के संबंध में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी बिना तथ्यों की जांच करे झूठे आरोप लगाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने साप्ताहिक बाज़ारों से शुल्क लेने के कार्य को निजी हाथों में नहीं दिया है और न ही इस तरह का विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी हमेशा झूठ की राजनीति करती है ये लोग दूसरों पर बिना तथ्यों को जाँचे आरोप लगाते हैं। जोगी राम जैन ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम हमेशा नागरिकों के हितों के लिए कार्य करती है और साप्ताहिक बाज़ारों के संबंध में इस तरह का कोई निर्णय अभी तक निगम द्वारा नहीं किया गया है।

अरावली क्षेत्र का होगा विकास सरकार ने कसी कमर

अरावली क्षेत्र पूरे राज्य का लगभग 25 फीसदी हिस्सा

नई दिल्ली, 8 अगस्त **(एजेंसी)।** पंजाब भूमि संरक्षण एक्ट 1900 के तहत हरियाणा राज्य की 25 फीसदी ज़मीन जो कि वन क्षेत्र में आती है को विकसित नहीं किया जा सकता। इससे आज के परिदृश्य में रोजगार, भूमीगत अधोसंरचना, और राज्य में विकास के अवसर कम पड़ते नज़र आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1094543 हेक्टेयर लगभग 10945 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह वन क्षेत्र से घिरा हुआ है यह पूरे राज्य का लगभग 25 फीसदी हिस्सा है। किसी भी राज्य में 25 फ़ीसदी हिस्से में यदि विकास नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से ना ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप हो पाएगा न ही रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे और ना ही राज्य में खाद्य सामग्री उत्पन्न हो पाएगी। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा ऐसा कदम जिससे वन भी संरक्षित रहें और मानव की भी क्रमोन्नत उन्नति हो सके।

100 साल पहले बनाए गए नियम को संशोधित करते हुए हरियाणा सरकार ने पंजाब भूमि संरक्षण एक्ट 1900 को संशोधित किया जिससे कि 25 फीसदी जंगली हिस्से में भी कुछ हिस्से में विकास के काम किए जाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर को डिवेलप किया जाए, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, कुछ रिहायशी कॉलोनी अभी बनाई जाएं, कुछ जमीन औषधियों और विभिन्न प्रकार की खेती के लिए भी इस्तेमाल की जा सके। इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी पेश किया जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की 25 फीसदी जंगली जमीन पर किसी भी प्रकार के विकास पर रोक लगा कर रखी है।

लेकिन यहां एक बात समझना बेहद ही जरूरी है कि राज्य में जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है 100 साल पहले आबादी का आंकड़ा कुछ और था 100 साल बाद आबादी का आंकड़ा कुछ और है संसाधन सीमित होते चले जा रहे हैं आबादी बढ़ती चली जा रही है ऐसे में मूलभूत मानव के जो अधिकार हैं रोटी, कपड़ा और मकान वह भी सरकार को मौहिया कराना चाहिए और इसी के मद्देनजर सरकार ने इस एक्ट में संशोधन किया है। एक्ट में संशोधन के बाद मामला फिर एक बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है।

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जंगल को बचाने के लिए भी और मानव को बचाने के लिए भी गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। लेकिन इतना तय है कि हमें जंगल भी बचाने हैं और मानव के अधिकारों को भी बचाना है हमें सतत निरंतर विकास भी करना है लेकिन प्रकृति सम्मत विकास होना चाहिए यदि जंगली क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्र डिवेलप होता है तो ये उन डेवलपर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वह जंगली क्षेत्र को भी उतना ही संरक्षित रखें जितना जरूरी है।

9 साल की दलित बच्ची को तुरन्त न्याय मिले व अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले : चौ. अनिल कुमार

अरविंद केजरीवाल ऐसी कोई भावना नहीं रखते हैं जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। दिल्ली में 55 पॉस्को अदालतों में केवल 37 लोक अभियोजक हैं, हालांकि प्रत्येक अदालत में 2 के हिसाब से कुल 110 लोक अभियोजकों की आवश्यकता हैः-चौ. अनिल कुमार

नई दिल्ली, 8 अगस्त **(एजेंसी)।** दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली छावनी के पुरानी नंगल राय गांव में 9 वर्षीय दलित लड़की के साथ हुऐ बलात्कार और हत्या ने एक बार फिर से दिल्ली को शर्मशार करते हुऐ यह दिखा दिया है कि बलात्कारियों व ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की कितनी जरूरत है और लोक अभियोजकों की संख्या बढ़ानी कितनी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पॉस्को अदालतों में लोक अभियोजकों की कमी पीड़ितों को न्याय दिलाने में अत्यधिक देरी कर रही है, क्योंकि अरविंद सरकार ने पॉस्को अदालतों में सरकारी अभियोजकों के 73 रिक्त पदों को भरने में कोई तत्परता नहीं दिखाई है। चौ. अनिल कुमार ने कहा कि न्याय में देरी न्याय से वंचित है लेकिन सीएम अरविंद ऐसी कोई भावना नहीं रखते हैं जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में 55 पॉस्को अदालतों में केवल 37 लोक अभियोजक हैं, हालांकि प्रत्येक अदालत में 2 के हिसाब से कुल 110 लोक अभियोजकों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, अरविंद सरकार ने केवल 18 अतिरिक्त लोक अभियोजकों की नियुक्ति की, 73 पद अभी भी खाली हैं। चौ. अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने 70-सूत्रीय घोषणापत्र में 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब कम से कम 63 फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है लेकिन केवल 13 ही चालू हैं। चौ. अनिल कुमार ने कहा कि मौजूदा हालातों में लोक अभियोजकों पर अत्यधिक काम का बोझ ड़ला दिया गया है, प्रत्येक अभियोजक को 6500 मामलों को संभालना पड़ता है।

समझौता एक वर्षीय एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स ऑटोमोटिव मेकाट्रोनिक्स एडीएएम की शुरुआत

डीएसईयू के छात्रों को मर्सिडीज बेंज इंडिया अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट सपोर्ट देगी

नई दिल्ली, 8 अगस्त (एजेंसी)। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के डीएसईयू ओखला कैंपस में ऑटो मेकाट्रोनिक्स रिसर्च सेंटर ईएमआरसी के तहत एक वर्षीय एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स ऑटोमोटिव मेकाट्रोनिक्स एडीएएम की शुरुआत करने के लिए मर्सिडीज बेंज इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विश्वविद्यालय और मर्सिडीज बेंज इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित एमओयू एक्सचेंज समारोह में कस्टमर सर्विस एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स के उपाध्यक्ष शेखर भिड़े ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मर्सिडीज बेंज इंडिया के लिए दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कार्य करना सम्मान की बात है।

इस डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी,एम्बेडेड सिस्टम, उन्नत ऑटोमोबाइल सिस्टम,इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण शामिल होगा, जो छात्रों के समग्र विकास में सहायता करेगा। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि ट्रेनर्स को भी इस कोर्स के तहत कैपेसिटी बिडलिंग एक्सरसाइज से लाभ होगा। छात्र और ट्रेनर्स दोनों गेस्ट लेक्चर में भाग लेंगे, क्षेत्र के कैंपस विजिट पर जाएंगे और इन गतिविधियों से छात्र प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में अपना कोर्स पूरा कर लेने पर छात्र प्लेसमेंट के बारे में सबसे अधिक चिंतित होते हैं। इसलिए, डीएसईयू के साथ मर्सिडीज बेंज इंडिया सभी छात्रों को प्लेसमेंट में सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अगले महीने कोर्स में दाखिले की घोषणा होने की उम्मीद है। इस मौके पर डीएसईयू की वाईस चांसलर प्रो. डॉ. नेहारिका वोहरा ने कहा कि हमें इस तरह के एक प्रतिष्ठित और अनुभवी संगठन के साथ

मिलकर कार्य करने की बेहद खुशी है। डीएसईयू छात्रों के साथ-साथ फैकल्टी को भी इस कोर्स से बहुत लाभ होगा और इस क्षेत्र की अंतर्दृष्टि एक नए दृष्टिकोण से प्राप्त होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय की स्थापना छात्रों को अनुभव प्राप्त करने और उद्योग से संबंधित कौशल विकसित करने के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करने के विचार के साथ की गई है। यह साझेदारी विश्वविद्यालय द्वारा उद्योगों और छात्रों के बीच के गैप को कम करने की ओर उठाया गया एक कदम है। वीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कई छात्रों का बचपन से सपना होता है कि वे खुद से कार को डिजाइन और विकसित करें। हालाँकि, यह सपना कई लोगों के लिए कभी सच नहीं होता है। इस साझेदारी के माध्यम से, विश्वविद्यालय छात्रों को उनके सपनों को प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना चाहता है। साथ ही, उन्हें भविष्य के इंटरप्रेन्योर एवं लीडर्स बनने में सहायता करना चाहता है। उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी व्यक्त की कि इस कोर्स की ट्रेनिंग में मर्सिडीज बेंज पुणे प्लांट की एक फैक्ट्री विजिट भी शामिल होगी, जो छात्रों का विश्वास बढ़ाएगी और उन्हें उद्योग के पेशेवरों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

ऑटोमोटिव मेक्ट्रोनिक्स एडीएएम कोर्स में एडवांस डिप्लोमा, मर्सिडीज-बेंज इंडिया की एक पहल है, जो ऑटोमोटिव क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा की आवश्यकता को पूरा करेगी और नवीनतम विश्व स्तरीय उपकरणों का उपयोग करके ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी पर इच्छुक इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगी। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने मेक्ट्रोनिक्स प्रशिक्षण स्कूल वर्ष 2006 में, प्रशिक्षित सेवा कर्मी एवं इंजीनियर्स प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया था।

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मूल कंपनी डेमलर एजी, जर्मनी ने मर्सिडीज-बेंज इंडिया और मर्सिडीज-बेंज इंडिया डीलरशिप नेटवर्क के साथ मिलकर कार्यक्रम शुरू किया और छात्रों को मर्सिडीज-बेंज प्रौद्योगिकी और नवाचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया। मर्सिडीज-बेंज इंडिया के साथ डीएसईयू का लक्ष्य कौशल प्रशिक्षण में मौजूदा गैप को कम कर युवाओं और उद्योग के लिए फायदे का सौदा बनाना है। विश्वविद्यालय कौशल के मौजूदा प्रतिमान को बदलकर, स्किलिंग को आकांक्षात्मक बनाना और सभी को कौशल, अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग के अवसर प्रदान करना चाहता है।

संपादकीय

विपक्षी एकता की कवायद

पिछले कुछ दिनों से विपक्षी राजनीतिक दलों ने महंगाई, कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर एकजुट होने का प्रयास तेज कर दिया है। इस कड़ी में बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के न्योते पर कई प्रमुख दलों के नेता कांस्टीट्यूशन क्लब में नाश्ते पर मिले। हालांकि इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप लोगों को आमंत्रित करने का एकमात्र मकसद विपक्ष को एकजुट करना है। इन्हीं दिनों कुछ राजनीतिक दलों के नेता साइकिल से संसद गए। यह साइकिल यात्रा प्रतीकात्मक थी। ये नेता सरकार को यह बताना चाहते थे कि पेट्रोल और ड़ीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता बहुत परेशान है। शायद विपक्ष को यह लगता है कि महंगाई, कृषि कानून और पेगासस जासूसी कांड़ बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं और इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर भाजपा को परास्त किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से विशेषकर प. बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी एकता को लेकर बहुत उत्साहित हैं। ममता बनर्जी के अलावा अन्य कुछ नेता भी गैर भाजपा दलों को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए हैं। दरअसल, भाजपा की बढ़ती ताकत से विपक्षी खेमे में अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर खतरा महसूस होने लगा है। यही वजह है कि अभी से ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों 2024 के लोक सभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। लिहाजा राहुल गांधी की राजनीतिक महञ्चवाकांक्षा को अच्छी तरह से समझा जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर ममता की सक्रियता बता रही है कि वह भी अब राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी हैं। पिछले दिनों उनकी दिल्ली यात्रा से इस बात की पुष्टि होती है। अहम सवाल यह है कि गैर भाजपा दलों की यह एकजुटता किसी संभावित राजनीतिक गठबंधन में तब्दील हो पाएगी या नहीं। अहम सवाल यह भी है कि एनड़ीए के विरुद्ध अगर कोई गठबंधन बनता है तो उसका नेता कौन होगा? विपक्ष के तीन बड़े नेताओं शरद पवार, ममता और राहुल के बीच जब तक गठबंधन के नेता पद के मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है तब तक ऐसे किसी भी गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती।

नयी शुरुआत हो

टोक्यो ओलंपिक में गांव व छोटे शहरों से आये खिलाड़ियों ने अविश्वसनीय प्रदर्शन करके देश का गौरव बढ़ाया है। बेहद मुश्किल हालातों और अभावों की तपिश से निखरी इन प्रतिभाओं को चमकाने में हमारे खेलतंत्र का कम व इन खिलाड़ियों के निजी प्रयास महत्वपूर्ण रहे। एक जुनून था अपने खेल में कुछ कर गुजरने का। दूरदराज के गांवों से निकले इन खिलाड़ियों ने खून-पसीना एक करके वैश्विक पहचान हासिल की। इनमें सोनीपत के नाहरी गांव के पहलवान रवि दहिया, मुक्तसर के कबरवाला गांव की डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत, असम के गोलाघाट जनपद के बरो मुखिया गांव की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाईं शामिल हैं। भारोत्तोलन में सबसे पहले रजत पदक जीतने वाली मणिपुर की मीराबाई चानू जब निकट के शहर में अभ्यास के लिये जाती थी तो धनाभाव में ट्रकों से लिफ्ट लेती थी। उसने पदक लेकर लौटने पर कई ट्रक चालकों को सम्मानित करके कृतज्ञता जाहिर की। इन खिलाड़ियों का संघर्ष कितना बड़ा है? वे बेहद मुश्किल हालातों से जूझकर देश के लिये तमगे लाते हैं। कुशल प्रशिक्षण व आधुनिक सुविधाओं से लैस पश्चिमी देशों के खिलाड़ियों से हारने के बाद मैदान में आंसू बहाते हमारे खिलाड़ी सपनों के बिखरने पर टूट जाते हैं। ये खिलाड़ी गरीबी, पितृसत्तात्मक समाज व अनेक पूर्वाग्रहों को परास्त करके खेलों में जी-जान लगा देते हैं। आखिर हम ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब कर पायेंगे? समय आ गया है कि देश में खेलों के अनुकूल वातावरण तैयार किया जाये। आने वाले दशकों के लक्ष्य हासिल करने हेतु व्यावहारिक रोडमैप तैयार किया जाये, जिससे हमारे खिलाड़ी देश की झोली सोने-चांदी के पदकों से भर सकें। निस्संदेह बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास के लिये आधुनिक संसाधन जुटाने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में अप्रत्याशित सुधार होता है। खिलाड़ी जहां मौलिक प्रतिभा और अभ्यास से अर्जित प्रतिभा से लक्ष्य हासिल करते हैं, वहीं सक्षम कोच व साधन भी जरूरी हैं।

निस्संदेह वक्त के साथ विश्वस्तरीय सुविधा, प्रशिक्षण व संसाधनों की खेलों में पदक जीतने में बड़ी भूमिका हो गई है। खेल के बारीक गुर और आधुनिक तकनीक भी खेलों की दशा-दिशा तय करती है। टोक्यो ओलंपिक व पहले की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में अविश्वसनीय सुधार हुआ है, जिन्होंने विदेशों में या देश में विदेशी कोचों के जरिये प्रशिक्षण लिया। भारत में जहां हमारी मौलिक प्रतिभाएं रहती हैं, वहां खेल प्रशिक्षण की मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। इन प्रतिभाओं को घर के पास खेल अकादमियां नहीं मिलती, दूर के शहर में सुविधा मिलती है तो उनके पास अकादमियों की फीस भरने के पैसे नहीं होते। गांव-देहात के कम आय वर्ग के बच्चे दिल्ली, बेंगलुरु, पटियाला और चेन्नई जैसी अकादमी वाले शहरों में लंबे समय तक रहकर प्रशिक्षण लेने में सक्षम भी नहीं होते। कई खिलाड़ियों को सैकड़ों किलोमीटर केवल अभ्यास के लिये रोज आना-जाना पड़ता है। इस दिशा में सुधार के लिये दृढ़ इच्छाशक्ति भी राजनेताओं में नजर नहीं आई। निस्संदेह रातों-रात ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी तैयार नहीं होते। दशकों पहले खेलतंत्र विकसित करना होता है। जरूरी है खिलाड़ियों को घर के नजदीक खेल का कौशल सुधारने वाला बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाये। इसके अभाव में कई खेल प्रतिभाएं बीच में खेलना छोड़ देती हैं। हर जिले में राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें। अपने मूल स्थानों पर ये प्रतिभाएं बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। उन्हें पढ़ाई में कुछ छूट देने के साथ आर्थिक सहायता भी मिले ताकि वे बेफिक्र होकर खेल पर ध्यान लगा सकें।

प्रवीण कुमार सिंह

विदेशी मीडिया

अहम मुद्दों पर ध्यान दें

हर बार एक नया मंत्री आता है, और नई कार्य-योजना पेश कर देता है, मानो उसके पूर्ववर्तियों ने मंत्रालय से जुड़ी समस्याओं के हल की दिशा में कुछ किया ही नहीं। साल 2017 के आम चुनाव के बाद केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में बनी पहली सरकार से अब तक स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय छह मंत्रियों को देख चुका है। यह इकलौता मंत्रालय है, जिसने पिछले साढ़े तीन साल में सबसे अधिक नेतृत्व परिवर्तन देखा। इसे कोविड-19 महामारी के कुप्रबंधन के लिए चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी, बल्कि कुछ मंत्रियों को तो अनियमितता में संलिप्त होने के आरोप में तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली को बदलना पड़ा था। ओली द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपना सारा ध्यान ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और वैक्सीन जैसे मेडिकल उपकरणों की खरीद पर ही लगाए रखा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 से मरने वालों में ज्यादातर की मौत ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी के कारण हुई। शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली सरकार के वजूद में आने तक सिर्फ पांच प्रतिशत आबादी को टीके लगे थे। पदभार संभालने के अगले ही दिन नवनियुक्त स्वास्थ्य एवं जनसंख्या राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ ने एलान किया था कि अक्तूबर के मध्य तक उनका मंत्रालय दो करोड़ टीकों की व्यवस्था करेगा। इनमें से लगभग 97 लाख टीके पहले ही आ चुके हैं। आने वाले दो हफ्तों में चीन से सहायता स्वरूप मिली वीरो सेल की 16 लाख और जापान से मदद के रूप में मिली एस्ट्राजेनेका की 16 लाख खुराकें आ जाएंगी। कुल मिलाकर, जनवरी के मध्य तक नेपाल में तीन करोड़ 23 लाख खुराकें उपलब्ध होंगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सभी सरकारी अस्पतालों से टीकाकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। लेकिन विदेश में काम के लिए जाने को तैयार नौजवान टीके लेने के बावजूद अपने प्रमाणपत्र पर अनिवार्य 'क्यूआर कोड' के वास्ते भटक रहे हैं। मेजबान देशों से वर्क परमिट और वीजा पा चुके प्रवासी कामगारों को आखिर कब क्यूआर कोड वाला प्रमाणपत्र जारी होगा? मंत्रालय को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

कश्मीरियत से गुलजार होता कश्मीर

कश्मीर की हर सरकारी इमारत पर अब तिरंगा शान से लहराता है। अनुच्छेद 370 की विदाई के दो साल बाद कश्मीर में आया ये सबसे बड़ा बदलाव भी है और बदलाव की सबसे खुशनुमा तस्वीर भी।

दो साल पहले तक ये बात कल्पना से भी परे थी। हर सरकारी कार्यक्रम, बैठक और समारोह में राष्ट्रीय ध्वज और जम्मू-कश्मीर राज्य का झंडा दोनों लगाए जाते थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को अलग विधान, अलग निशान की व्यवस्था समाप्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर का अलग ध्वज भी पुराने दिनों की याद बनकर रह गया है। इसकी जगह नये कश्मीर का मुकद्दर बनते जा रहे एक और बदलाव ने ले ली है, जो इस खुशनुमा तस्वीर में चार चांद लगा रहा है। कल तक जिस फिजां पर बारूदी गंध का कब्जा था, आज वहां केसर की क्यारियों की हुकूमत है। आतंक का गढ़ अब विकास का नया ठिकाना बन रहा है और युवाओं के हाथ अब कत्ल के लिए नहीं, बल्कि कलम थामने के लिए उठ रहे हैं।

दो साल पहले तक श्रीनगर के डाउनटाउन से लेकर पुलवामा तक के चौराहों पर पत्थरबाज तैनात रहते थे, लेकिन अब सब बदल चुका है। पथराव 85 फीसद तक घट गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक साल 2019 में 1,990 से अधिक पथराव की घटनाएं हुई थीं। वहीं साल 2020 में ऐसी 250 घटनाएं रिपोर्ट हुई। इस साल भी इक्का-दुक्का मामलों को छोड़कर पत्थरबाजी की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। पत्थरबाजी की बदली तस्वीर का एक सिरा सरहद की बदली तासीर से भी जुड़ता है, जहां फ्री-हैंड मिलने के बाद हमारे जवान आतंकियों के लिए काल बनकर टूट रहे हैं। मई 2018 से जून 2021 तक यानी तीन साल में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 400 मुठभेड़ हुई, जिनमें 630 आतंकियों को मार गिराया गया। इस साल 31 जुलाई तक सात पाकिस्तानी आतंकियों समेत 90 से ज्यादा दहशतगदरे को ढेर किया जा चुका है।

> कल तक जो कश्मीरी युवा लक्ष्य के अभाव में बंदूक थाम लेते थे. वो अब कश्मीर के विकास में अपनी मंजील हासिल कर रहे हैं। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में मार्च. 2021 के अंत में बेरोजगारी की दर घटकर नौ फीसद रह गई है। ये आंकड़ा गोवा, दिल्ली और राजस्थान से बेहतर है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इस आंकड़े पर सवाल उठाती रहती हैं, लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तो अगले पांच साल में बेरोजगारी को पूरी तरह खत्म करने की बात कह रहे हैं.

जाहिर है कि 370 हटाए जाने के बाद अलगाववादियों और आतंकियों के बहकावे में आए कश्मीर के नौजवानों ने आतंक का हश्र और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के सरकार के प्रयासों से प्रभावित होकर पत्थर उठाना छोड़ दिया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन किसी तरह की गफलत में नहीं रहना चाहता। इसलिए पिछले हफ्ते ही उसने पत्थरबाजों पर और सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें सरकारी नौकरी नहीं देने और उनका पासपोर्ट वेरिफाई नहीं करने का फैसला लिया है।

दरअसल, कश्मीर में बदलाव की बयार ने समाज के जिस वर्ग को सबसे ज्यादा बदला है, वो यहां के युवा ही हैं। मौजूदा व्यवस्था युवाओं को कश्मीरी समाज का सामान्य हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के तौर पर देख रही है। इसकी वजह भी है। कश्मीर में 35 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं की आबादी 65 फीसद है और वहां दशकों की अस्थिरता से सबसे ज्यादा प्रभावित भी यही वर्ग रहा है। बेहतर संभावनाओं की तलाश में कश्मीरी युवा एक परंपरा की तरह पलायन करने के लिए अभिशप्त रहे हैं। उस नुकसान की यथासंभव भरपाई के लिए प्रशासन ने 'बैक टू विलेज' कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 50 हजार युवाओं को स्व-रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बड़ी संख्या में कश्मीरी युवाओं को अपनी मातृभूमि में अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल रहा है। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 200 करोड़ के फंड से जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। कल तक जो कश्मीरी युवा लक्ष्य के अभाव में बंदूक थाम लेते थे, वो अब कश्मीर के विकास में अपनी मंजिल हासिल कर रहे हैं। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में मार्च, 2021 के अंत में बेरोजगारी की दर घटकर नौ फीसद रह गई है। ये आंकड़ा गोवा, दिल्ली और राजस्थान से बेहतर है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इस आंकड़े पर सवाल उठाती रहती हैं, लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तो अगले पांच साल में बेरोजगारी को पूरी तरह खत्म करने की बात कह रहे हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने में नई उद्योग नीति सबसे बड़ा माध्यम बन सकती है। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के तहत इसी साल जनवरी में राज्य को 28 हजार चार सौ करोड़ का इंसेटिव मिला है। माना जा रहा है कि इस तरह की उद्योग नीति किसी प्रदेश के पास नहीं है। सरकार को इससे 45-50 हजार निवेश आने की उम्मीद है, जिससे ब्लॉक और दूरदराज के इलाकों का औद्योगिक विकास हो सकेगा और आठ से नौ लाख और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

पिछले दो साल को देखें, तो कश्मीर में तरक्की की रफ्तार ऐसी दिखी है जैसे किसी युद्ध की तैयारी चल रही हो। जम्मू-कश्मीर में अब आईआईटी, आईआईएम हैं। दो-दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, निफ्ट है। दो एम्स का निर्माण हो रहा है। दो कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। सात पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं। युवाओं के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से फाइनेंशियल सर्विस की ट्रेनिंग और टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से कौशल विकास का काम चल रहा है। युवाओं की ही तरह महिलाएं भी बदलाव के केंद्र में हैं। इस दिशा में महिला उद्यमियों के लिए 'हौसला' योजना एक ऐतिहासिक प्रयास कहा जाएगा। कश्मीर में महिलाओं का समाज में दर्जा बेहतर है और शिक्षा को लेकर काफी सजगता भी है। हौसला योजना इसी तथ्य को देखकर बनाई गई लगती है, क्योंकि यह पढ़ी-लिखी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान और लीडरशिप में हिस्सेदारी का मंच देती है। इस योजना के कारण कश्मीरी महिलाओं की आईटी, ई-लर्निंग, ई-कॉमर्स, टेलीमेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ी है। विशेष राज्य का दर्जा वापस होने के बाद जम्मू-कश्मीर में सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रयास भी तेज हुए हैं। इसके तहत ही वहां पहले पंचायत और फिर बीडीसी चुनाव कराए गए। लोकतंत्र के पर्व पर आतंक की छाया दूर-दूर तक नहीं दिखी, बल्कि इसमें शिरकत करने के लिए स्थानीय लोग बेखौफ होकर बाहर निकले। कई जगह पर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों तक ने मतदान में हिस्सा लिया। इस प्रकिया की सफलता से यह तथ्य भी स्थापित होता है कि स्थानीय लोगों का इस बात पर भरोसा मजबूत हो रहा है कि जम्हूरियत कोई जुमला नहीं, बल्कि कश्मीर की जरूरत है। कश्मीरी पंडितों की वापसी का मसला जरूर अभी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है, लेकिन ये मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सवाल विस्थापितों की सुरक्षा का है और प्रशासन की सोच ऐसी है कि ये वापसी तब तक संभव नहीं दिख रही, जब तक उनके घरों की मरम्मत नहीं हो जाती। विकल्प के तौर पर प्रशासन कुलगाम, बड़गाम, गांदरबल, शोपियां, बांदीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में बड़े पैमाने पर ट्रांजिट आवास बना रहा है और इनमें से ज्यादातर के लिए नवम्बर, 2022 तक की समय सीमा भी रखी गई है।

संक्षेप में कहें, तो कश्मीर में कश्मीरियत बहाल करने के लिए सरकार ने पूरी तरह कमर कस ली है। इस कश्मीरियत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मुरीद हैं। प्रधानमंत्री खुद कई सार्वजनिक मौकों पर कह चुके हैं कि कश्मीर की समस्या न गोली से सुलझने वाली है, न गाली से बल्कि ये सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगाने से। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन इसी लक्ष्य को साधने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए पिछले दो साल में नीति, नीयत और सही निर्णय के संगम से जो बदलाव देखने को मिले हैं, उससे यही भरोसा मजबूत होता है कि कश्मीर में कश्मीरियत गुलजार करने के प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

वैश्विकी

सुरक्षा परिषद में मोदी

भारत अगस्त महीने में गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल रहा है।

सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने वर्ण क्रम के आधार पर स्थायी और गैर स्थायी सदस्य एक महीने के लिए संभालते हैं। भारत के लिए यह अध्यक्षता इस रूप में महत्त्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 9 अगस्त को सुरक्षा परिषद की उच्चस्तरीय चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। यह पहला अवसर होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री इस विश्व संस्था की अध्यक्षता करेगा। भारत विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से यह बड़ी उपलब्धि होगी। विगत महीनों में पश्चिमी देशों की मीडिया और बौद्धिक वर्ग ने भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार अभियान चलाया है। प्रधानंमत्री मोदी के विरुद्ध किसी-न-किसी मुद्दे को लेकर निशाना साधा गया है। ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की गई है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विशेषण का अधिकारी नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निर्वाचित शासनाध्यक्ष न होकर वास्तव में अधिनायकवादी हैं। ऐसे में मोदी का सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालते हुए विश्व बिरादरी को संबोधन गलत धारणाओं को दूर करने में सहायक बनेगा।

प्रधानमंत्री मोदी समुद्री सुरक्षा और उसे सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विचार व्यक्त करेंगे। चर्चा के विषय के रूप में समुद्री सुरक्षा को चुना जाना मौजूदा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के अनुरूप है। दक्षिणी चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और मोटर वाहन दुनिया के सामने प्रमुख एजेंडा बना हुआ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभर रहा चतुगरुट (क्वाड) भी इससे जुड़ा है। मोदी इस विषय पर विचार करते समय सीधे या परोक्ष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका और अन्य देशों के साथ सहयोग का जिक्र करेंगे। यह क्वाड के सदस्य देशों की ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग संगठन आसियान के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का भी अवसर होगा। मोदी सुरक्षा परिषद के मंच से चीन की समुद्र और भूमि पर जारी विस्तारवादी गतिविधियों की ओर संकेत कर सकते हैं।

भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान तीन बिंदुओं समुद्री सुरक्षा, शांति अभियान और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को केंद्र में रखा है। अध्यक्ष के रूप में भारत ने पिछले शुक्रवार को अफगानिस्तान की घटनाक्रम पर चर्चा का आयोजन किया। सभी सदस्य देशों ने अफगानिस्तान के तेजी से बिगड़ रहे हालात पर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगाह किया कि काबुल पर तालिबान का कब्जा होना अफगानिस्तान और आसपास के देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तालिबान का दावा है कि दो तिहाई अफगानिस्तान उनके कब्जे में है। तालिबानी कब्जे वाले क्षेत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार यह आतंकवादी संगठन अपनी पुरानी मध्ययुगीन विचारधारा और बर्बर कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। बीस साल बाद प्राचीन सभ्यता वाला एक उदारवादी देश माने जाने वाला अफगानिस्तान फिर बर्बर युग में प्रवेश कर सकता है। सबसे दुखद बात यह है कि विभिन्न देशों को अधिक चिंता इस बात को लेकर है कि तालिबान के कब्जे के बाद उनके लिए कोई सुरक्षा खतरा पैदा न हो। रूस ने उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सुरक्षा बलों के साथ आतंकवाद विरोधी अभ्यास शुरू किया है। चीन भी ऐसे ही कदम उठा रहा है। हालांकि चीन को अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान पर भरोसा है कि वह तालिबान आतंकवादियों और उइगर मुस्लिम पृथकतावादियों को शिजियांग प्रांत का रुख नहीं करने देगा।

सबसे विषम स्थिति भारत के लिए पैदा होने वाली है। इस समय लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन तथा पाकिस्तान के जिहादी तालिबान के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। तालिबान के काबुल पर काबिज होने के बाद वे जम्मू-कश्मीर को अगले जिहाद का केंद्र बनाएंगे। जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई इन आतंकवादियों को दिशा-निर्देश देगी। भारत में पहले से ही घरेलू राजनीति में विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। घरेलू राजनीति में विभाजन और संघर्ष की समाप्ति के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

स्मरण

पदमा सचदेव-हिन्दी की सेवा करने वाली डोगरी लेखिका

हिन्दी को जन-जन की भाषा बनाने में गैर-हिन्दी क्षेत्रों के लेखकों और अध्यापकों ने भी भरसक अपना निस्वार्थ भाव से योगदान दिया है।

इनके सहयोग के बिना हिन्दी देश के चप्पे- चप्पे में शायद बोली या समझी भी ना जाती। इस तरह के लेखकों में मूलतः डोगरी की कवयित्री और लेखिका पद्मा सचदेव का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता रहेगा। उन्होंने भाषा सेतुबंधन का अनुकरणीय कार्य किया। उन्होंने डोगरी के अलावा हिन्दी में भी लगातार रचना धर्मिता का कार्य निर्वाह किया। उनके निधन से हिन्दी ने अपना एक बड़ा हितैषी को खो दिया है।

दरअसल, पंजाब और जम्मू क्षेत्र में हिन्दी सेवी लंबे समय से चलते आ रहे हैं। पदमा सचदेव जम्मू से थीं। अगर बात पंजाब की करें तो भीष्म साहनी, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, नरेन्द्र मोहन, नरेन्द्र कोहली, प्रताप सहगल समेत दर्जनों पंजाबी के लेखक देश कें बंटवारे से पहले और बाद में हिन्दी में रचनाकर्म करते रहे। यह समृद्ध परंपरा अब भी जारी है। एक समय तो लाहौर हिन्दी साहित्य का बड़ा केंद्र हुआ करता था। पंजाब से सटे जम्मू में पदमा सचदेव के अलावा भी बहुत से लेखक अपनी मातृभाषा डोगरी के साथ-साथ हिन्दी में लगातार लिखते ही रहे हैं। पाकिस्तान बनने के साथ ही वहां जम्मू से सटे स्यालकोट में और पंजाब सूबे में हिन्दी को जबरन खत्म कर दिया गया।

यह सारा क्षेत्र हिन्दी भाषी न होने पर भी हिन्दी को लेकर स्नेह तथा सम्मान का भाव रखता था। खैर, जम्मू और हमारे पंजाब में हिन्दी की जड़ें तो बहुत ही गहरी हैं। वहां अब भी हिन्दी में श्रेष्ठ साहित्य रचा ही जा रहा है। पदमा सचदेव जी के बहाने ही सही हम बात कर रहे हैं हिन्दी के उन सेवियों की जो गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। अगर हम दक्षिण भारत की ओर का रु ख करें तो वहां पर हिन्दी प्रचार सभा ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार में कमाल का योगदान दिया है। सन 1918 में मद्रास में 'हिन्दी प्रचार आंदोलन' की नींव रखी गई थी और उसी वर्ष स्थापित हिन्दी साहित्य सम्मेलन कार्यालय आगे चलकर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के रूप में स्थापित हुआ। वर्तमान में इस संस्थान के चारों दक्षिणी राज्यों में प्रतिष्ठित शोध संस्थान है और बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय मूल के लोग इस संस्थान से हिन्दी में दक्षता प्राप्त कर ज्यादातर दक्षिण राज्यों में या देश के अन्य भागों में जाकर भी हिन्दी की सेवा कर रहे हैं।

हाल ही में ओलंपिक खेलों में भारत को वेटिलफ्टिंग का सिल्वर मेडल जितवाने वाली चानू मीराबाई तथा मुक्केबाज मेरीकॉम के भी इंटरव्यू देखे होंगे। ये सभी धारा प्रवाह हिन्दी बोलती हैं। अगर पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दी खूब बोली समझी जा रही है तो इसका श्रेय वहां के जुझारू हिन्दी प्रेमियों को जाता है। पूर्वोत्तर भागों में हिन्दी को स्थापित करने में सबसे पहले गांधी जी ने ही पहल की थी। गांधी जी ने असमिया समाज को हिन्दी से परिचित कराने के लिए पूर्वोत्तर में हिन्दी इसलिए भी आराम से स्थापित हो गई, क्योंकि माना जाता है कि जिन भाषाओं की लिपि देवनागरी है, वह भाषा हिन्दी न होते हुए भी उस भाषा के जरिए ही हिन्दी का आसानी से प्रचार हो जाता है।

जैसे कि अरूणाचल में मोनपा, मिशि और अका, असम में मिरि, मिसमि और बोड़ो, नगालैंड में अडागी, सेमा, लोथा, रेग्मा, चाखे, तांग, फोम तथा नेपाली, सिक्किम में नेपाली लेपचा, भड़पाली, लिम्बू आदि भाषाओं के लिए भी देवनागरी लिपि ही है। पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। संस्थान के तीन केंद्र गुवाहाटी, शिलांग तथा दीमापुर में सक्रिय हैं। ये तीनों केंद्र अपने-अपने राज्यों में हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के विशेष कार्यक्रम चलाते हैं।

बहरहाल,पदमा सचदेव के निधन के साथ ही अब उनके राजधानी के बंगाली मार्केट के टोडरमल रोड स्थित घर में होने वाली साहित्यिक गोष्ठियों की यादें ही शेष रह गई हैं। पदमा सचदेव को उनके कविता संग्रह 'मेरी कविता मेरे गीत' के लिए 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें वर्ष 2001 में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। उन्होंने कविता तथा कहानी के अलावा उपन्यास, साक्षात्कार, निबंध और यात्रा वृतांत भी लिखे। उनकी शादी 1966 में 'सिंह बंधू' नाम से प्रचलित सांगीतिक जोड़ी के गायक सुरिंदर सिंह से हुई थी। पदमा सचदेव का मित्रता का दायरा बहुत विस्तृत था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी उनकी सहेली थीं। इस दोस्ती का परिणाम यह निकला कि लता मंगेशकर ने पदमा सचदेव के लिखे कुछ गीत भी गाए। पदमा सचदेव ने अपनी पुस्तक 'ऐसा कहां से लाऊं' में लिखा कि उन्हें (लता मंगेशकर) को जहर देकर मारने की भी एक बार कोशिश हुई थी। यह घटना 1962 की है। पद्मा सचदेव को लता मंगेशकर ने बताया था कि उस घटना के बाद वह काफी कमजोर हो गई थी और लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ी रहीं थी। हिन्दी पट्टी पदमा सचदेव के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगी। हिन्दी के विकास और विस्तार के लिए अभी पदमा सचदेव सरीखी अनेक शख्सियतों की जरूरत है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में लाना है : मनोहर लाल

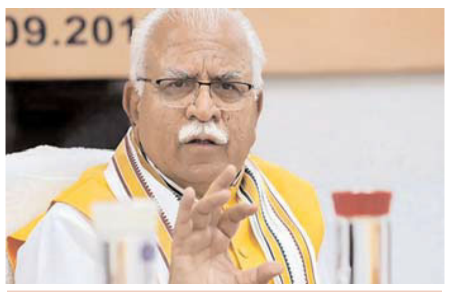

- मुख्यमंत्री ने सुशासन सहयोगियों के नए बैच को संबोधित किया
- सुशासन सहयोगी समाज के लिए सकारात्मक लक्ष्य लेकर आगे आएं

चण्डीगढ़, 8 अगस्त (एजेंसी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि शासन में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी प्रदेश की प्राथमिकताओं के अनुरूप बेहतर कार्य करेंगे। इसके साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचा कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री आज यहां सुशासन सहयोगियों के छठे नए बैच को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत अति गरीब एक लाख परिवारों की आय कम से कम 10 हजार रुपए मासिक करने का लक्ष्य है। इस योजना में 6 विभाग संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं जिनमें स्थानीय निकाय, श्रम, स्किल इण्डस्ट्रीज, स्वास्थ्य, एमएसएमई शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि 2024 तक प्रदेश के हर परिवार को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिलें और उनमें आर्थिक सम्पन्नता आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का नूंह जिला सबसे कमजोर है उसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढाना है।

उन्होंने कहा कि सुशासन सहयोगी समाज के लिए सकारात्मक और लाभप्रद विचारों वाले लक्ष्य लेकर आगे आएं, और उन्हें पूरा करने के लिए कार्य करें। यदि सही रास्तों पर चलते हैं तो कठिनाईयां आती हैं, लेकिन उनका हल निकालकर आगे बढना ही मुख्य ध्येय होना चाहिए। नए विचारों एवं सोच को लागू करना और उन्हें परिणामोन्मुखी बनाना ही जीवन का आधार होना चाहिए । उन्होंने कहा कि यदि जीवन में निराशा के क्षण आएं तो हिम्मत से काम लें और स्वामी विवेकानन्द की कहावत अनुसार उठो, जागो और आगे बढो-पर चलें और अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए समर्पित करें। जीवन में अनुशासन और समय के सदुपयोग पर पूरा ध्यान केन्द्रित रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन सहयोगी सरकार व जनता के बीच सहयोगी की अहम भूमिका निभाते हुए लक्ष्य के अनुरुप कार्य करें।

उन्होंने कहा कि इससे पहले बैच के सुशासन सहयोगियों ने बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, लिंगानुपात, सीएम विण्डो, सक्षम हरियाणा, ई-आफिस, स्वच्छ भारत अभियान आदि कार्यक्रमों में योगदान दिया। वर्तमान बैच में शासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, मॉडल संस्कृति स्कूल, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, परिवार पहचान पत्र आदि योजनाओं पर मुख्य रूप से कार्य किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन सहयोगी कोविड 19 नियंत्रण में भी भरपूर योगदान करेंगे। मुझे यकीन है कि नया बैच इस महामारी के कठिन समय में सरकार के कार्यक्रमों के लिए उपयोगी और प्रभावी भागीदार साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से गांवों में गलियां, कमरे आदि विकास कार्य करवाने के लिए व्यक्ति अपनी मांगे रख सकते हैं। संबंधित सरपंच, बीडीसी, जिला परिषद, विधायक की सिफारिश के बाद विभाग उसके निर्माण के लिए फिजिबलिटी, एस्टीमेंट एवं बजट तैयार करके कार्य की अनुशंसा करेगा। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी युग के में घर बैठे ही ऑनलाईन सिस्टम से लोगों को लाभ पहुंचाना है।

भाजपा सरकार में परचून की दुकान पर सामान की तरह बिक रही हैं नौकरियां : हुड्डा

- हरेक भर्ती का पेपर हो रहा है लीक, युवाओं के भविष्य से खेल रही है सरकार
- ओलंपिक में पेपर लीक करने की इवेंट होती तो भाजपा-जेजेपी सरकार को मिलता गोल्ड मेडल
- विधानसभा में उठाएंगे पेपर लीक घोटाले का मुद्दा

चंडीगढ़, 8 अगस्त (एजेंसी)। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी सरकार में परचून की दुकान पर सामान की तरह नौकरियां बिक रही हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे पेपर लीक घोटाले पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर ओलंपिक में पेपर लीक करने की कोई इवेंट होती तो हरियाणा की बीजेपी-जेजेपी सरकार को पक्का गोल्ड मेडल मिलता। पिछले कुछ सालों में शायद ही ऐसी कोई भर्ती हो जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। बिना उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की संलिप्तता के ये संभव नहीं है।

हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान 6 साल में दो दर्जन से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। एक ही साल में ग्राम सचिव और कांस्टेबल जैसी दो बड़ी भर्तियों का पेपर लीक होना आम बात नहीं है। बावजूद इसके आज तक सरकार ने किसी बड़े पदाधिकारी की जांच नहीं की करवाई। छोटे-मोटे कारिंदों पर खानापूर्ति की कार्रवाई करके मामले को रफादफा कर दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष ने याद दिलाया कि भर्तियों में धांधलेबाजी के चलते कुछ साल पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर छापेमारी हुई थी। तब पता चला था कि बीजेपी सरकार के दौरान हर भर्ती के रेट फिक्स हैं। 5 लाख रुपये से लेकर 10 और 20 लाख में नौकरियों को बेचा जा रहा था। लेकिन उस मामले में भी चंद छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई के अलावा जांच आगे नहीं बढ़ाई गई। यहां तक कि भर्तियों में धांधलेबाजी को लेकर खुद हाईकोर्ट सरकार को कई बार फटकार लगा चुकी है। कोर्ट ने भर्तियों में पारदर्शिता ना बरतने पर कई बार भर्ती आयोग को नोटिस जारी किए हैं। बावजूद इसके सरकार कोई सबक नहीं लेना चाहती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश का युवा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। साथ ही उसपर भर्ती घोटालों की मार पड़ रही है। जिन युवाओं को प्रदेश और देश की तरक्की में सहभागिता निभानी चाहिए थी, वो खुद भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रहे हैं। सरकार को युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पेपर लीक घोटाले के मामले को आने वाले विधानसभा सत्र में उठाएगी।

सार संक्षेप

श्रावण अष्टमी नवरात्र के दौरान हिमाचल में प्रवेश के लिए टीकाकरण, कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी

शिमला। सोमवार से शुरू हो रहे श्रावण अष्टमी नवरात्र के लिए हिमाचल प्रदेश में श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में प्रवेश की संभावना देखते हुए प्रदेश में प्रवेश के लिए टीके के दोनों डोज लगे होना अथवा 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह दिशानिर्देश जारी किये हैं। नौ अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलने वाले श्रावण अष्टमी नवरात्र के दौरान आसपास के प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहां के मंदिरों में आने की संभावना होती है। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार अलावा मंदिरों व धर्म स्थलों में 'मास्क नहीं तो दर्शन नहीं' की भी नीति अमल में लाई जाएगी।

डिजिटल बाल मेला में कई मुद्दों पर होगी चर्चा

जयपुर। राजस्थान में जयपुर में फ्यूचर सोसायटी, एलआईसी और आईडीबीआई बैंक की ओर से आयोजित हो रहे डिजिटल बाल मेला में इस सप्ताह बच्चे राजनीति के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। डिजिटल बाल मेला टीम की जाह्नवी शर्मा ने आज बताया कि बाल मेला के नवें सप्ताह का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें नौ अगस्त को चितौड़गढ़ सांसद सी.पी जोशी, 10 अगस्त को विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी, 11 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा, 12 अगस्त को इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड सोसायटी एनजीओ की प्रमुख हिमांशी गहलोत, 13 अगस्त को एलन जयपुर हेड आशिष अरोरा बच्चों संग संवाद करेंगे। उन्होंने बताया ककि बाल मेला के इस सीजन की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने 15 जून को की थी। सीपी जोशी ने कहा था कि इस बार बच्चे बच्चों की सरकार कैसी हो विषय पर चर्चा करें। इसके बाद उन्होंने बच्चों से वादा किया था कि बाल दिवस पर विशेष सत्र बच्चों का विधानसभा में बुलाया जाएगा। इस कड़ी में अब तक कई राजनेता बच्चों से चर्चा कर चुके हैं।

बूंदी में युवक की चाकू मारकर हत्या

कोटा। राजस्थान में बूंदी में आज रुपयों के लेन-देन को लेकर एक युवक ने दो अन्य युवकों को चाकू मार दिए जिसमें से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बूंदी निवासी रिजवान (23) और आबिद (24) को सुबह एक अन्य युवक बंटी ने चाकू मारकर घायल कर दिया जिसमें से रिजवान गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि आबिद को मामूली चोटें आई। दोनों को बूंदी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां रिजवान को मृत घोषित कर दिया। आबिद ने पुलिस को बताया कि रुपयों के लेनदेन को लेकर रिजवान और बंटी में कुछ हुआ था जिसको लेकर पिछले दिनों रिजवान ने बंटी से मारपीट की थी। इसी बात से खफा होकर बंटी ने आज चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी को तलाश कर रही है।

सुडोकू 5565 का हल

9	5	7	2	8	6	4	3	1
2	6	4	1	7	3	8	9	5
8	1	3	5	9	4	2	6	7
7	3	1	6	5	2	9	4	8
5	9	2	8	4	7	6	1	3
4	8	6	3	1	9	7	5	2
3	2	5	9	6	8	1	7	4
6	4	8	7	3	1	5	2	9

भाटला सामाजिक बहिष्कार मामले में सरपंच प्रतिनिधि सहित छह के गिरफ्तारी वारंट जारी

हिसार, 8 अगस्त (एजेंसियां)। भाटला सामाजिक बहिष्कार मामले में हिसार की एक विशेष अदालत ने एक सरपंच प्रतिनिधि समेत छह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत के जज अजय तेवतिया ने सामाजिक बहिष्कार के आरोपी सरपंच प्रतिनिधि पुनीत कुमार, रामचंद्र, राम सिंह, जयकिशन, लीला व सुमेरू पंडित के गिरफ्तारी वारंट जारी किए है।

सामाजिक बहिष्कार के पीड़ितों के अधिवक्ता रजत कलसन ने बताया कि 10 जुलाई 2017 को सरपंच समेत 7 लोगों के खिलाफ भाटला के दलितों का सामाजिक बहिष्कार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित हुई थी। श्री कलसन ने बताया कि टीम केवल एक आरोपी चंद्र फौजी को आरोपी बना कर अदालत में चालान दे दिया था तथा सरपंच प्रतिनिधि पुनीत कुमार समेत बाकी सभी छह आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ खिलाफ पीड़ित पक्ष ने तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत याचिका दायर कर उन्हें आरोपी बनाकर अदालत में तलब करने का अनुरोध किया था, जिस पर अदालत ने सरपंच प्रतिनिधि समेत छह लोगों को आरोपी मानते हुए उन्हें समन जारी किए थे। इसके बाद सरपंच प्रतिनिधि समेत छह आरोपियों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में खुद को तलब किए जाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ एक रिवीजन पिटिशन दायर की थी जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केवल एक तारीख के लिए रोक लगा दी थी। उसके बाद से कोरोना के कारण उक्त मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई तथा उक्त आदेश ही चला आ रहा था।

श्री कलसन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए 21 जुलाई 2021 को आदेश पारित कर कहा था कि जिन मामलों में हाईकोर्ट ने स्टे जारी किए हैं वह स्टे छह महीने के बाद प्रभावी नहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद पिछली छह अगस्त को भाटला समाजिक बहिष्कार मामले में हिसार की अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत में सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि धारा 319 के तहत तलब किए गए आरोपियों के जरिये हाईकोर्ट से हासिल स्टे केवल एक तारीख पेशी के लिए था तथा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अब उक्त स्टे प्रभावी नहीं है। जिसके बाद विशेष अदालत ने सरपंच प्रतिनिधि पुनीत कुमार समेत छह आरोपियों की गिरफ्तारी वारंट जारी किये।

पार्वती बांध से पानी छोड़ने से रास्ता बंद, फसल चौपट

धौलपुर, 8 अगस्त (एजेंसियां)। राजस्थान में दूसरे जिलों के बांधों के साथ कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी धौलपुर के किसानों की बर्बादी लिख गया।

सूत्रों ने आज बताया कि जिले का आंगई बांध भी किसानों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए तैयार है। शनिवार देर रात आंगई बांध भर जाने से छह गेट खोलकर 8063 क्यूसेक पानी बाहर निकाला गया है। एक महीने में दूसरी बार आंगई बांध के खोले जाने से फिर से पार्वती नदी उफान पर है। गत छह दिनों से धौलपुर जिले के ज्यादातर गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है।

पिछले पांच दिनों से जहां चंबल नदी में उफान की वजह से किसानों की फसलें खराब हुईं हैं, अब पार्वती नदी ने किसानों की चिंता को दोगुना कर दिया हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें खराब होने की कगार पर हैं । प्रशासन बाढ़

प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को राहत देने का काम कर रहा है। जिले के कस्बों को जोड़ने वाले कई रास्तों पर पानी रपट के ऊपर चलना शुरू हो चुका है।

सूत्रों ने बताया कि छह दिन पूर्व आंगई बांध के खोले जाने पर धौलपुर बसेड़ी मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक बार फिर से पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ जाने से सैपऊ कंचनपुर की रपट पर पानी आ गया है। सखवारा पुल से पार्वती नदी का पानी महज दो मीटर नीचे है। एहतियात के तौर पर निचले इलाकों में पुलिस को तैनात किया गया है। दोपहर बाद नदी पार करते समय एक सांड बह गया।

राजस्थान में कई जिलों में अतिवृष्टि के बावजूद आठ जिलों में बरसात की कमी

जयपुर, 8 अगस्त (एजेंसियां)। राजस्थान में मानसून की भारी वर्षा के कारण कई जिलों में अतिवृष्टि का सामना करना पड़ रहा है वहीं अभी भी आठ जिलों में लोग बरसात की कमी का भी सामना कर रहे है। कोटा, बांरा, बूंदी, सवाईमाधोपुर एवं झालावाड़ में अतिवृष्टि तथा अन्य नौ जिलों में सामान्य से अधिक एवं ग्यारह जिलों में सामान्य वर्षा के बावजूद बाड़मेर, डूंगरपुर, गंगानगर, जालोर, जोधपुर, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर जिले में बारिश की कमी बनी हुई हैं।

जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रदेश में गत एक जून से आठ अगस्त तक 346.85 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है जो सामान्य वर्षा 304.21 मिलीमीटर की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक हैं। गत वर्ष इस दौरान केवल 222.60 मिलीमीटर बारिश हुई थी। प्रदेश में बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा एवं सवाईमाधोपुर में अब तक असामान्य बरसात हो चुकी है तथा अजमेर, भरतपुर, चुरु, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, करौली, प्रतापगढ़ एवं टोंक में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है जबकि 11 जिलों अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, नागौर, पाली एवं सीकर में सामान्य बरसात हुई है।

प्रदेश में अब तक सर्वाधिक बरसात बारां जिले में रिकॉर्ड की गई जहां सामान्य वर्षा 445.20 मिलीमीटर के विरुद्ध 968.88 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है जो सामान्य से 117.6 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह कोटा में अब तक 833.44 मिलीमीटर वर्षा हुई जो सामानय से 102 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश के सातों संभागों में कोटा संभाग में अब तक सर्वाधिक सामान्य से 94.2 प्रतिशत अधिक वर्षा हो चुकी है। संभाग में 420.60 मिलीमीटर की जगह अब तक 816.74 मिलीमीटर बरसात हुई है जबकि सबसे कम जोधपुर संभाग में 155.06 मिलीमीटर बरसात हुई जो सामान्य से 35 प्रतिशत कम है। जोधपुर संभाग के छह जिलों में एक मात्र जैसलमेर जिला ही ऐसा हैं जहां सामान्य से 45 1 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई हैं।

एनसीएससी ने पंजाब सरकार से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में रिपोर्ट मांगी

- सरकार का दावा, जांच पूरी होती ही आयोग को भेजी जाएगी रिपोर्ट
- मंत्री को क्लीन चिट देने की खबर पर आयोग ने मांगी थी सफाई

होशियारपुर, 8 अगस्त (एजेंसियां)। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार से पोस्ट मैट्रिक घोटाले को लेकर रिपोर्ट तलब की है जिस पर कि पंजाब सरकार का कहना है कि रिपोर्ट अभी अधूरी है।

यह जानकारी आज यहां आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने दी। श्री सांपला ने बताया कि आयोग ने इसीके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज की रिपोर्ट की प्रति भी मांगी है। आयोग को प्रदेश सरकार की तरफ से बताया गया है कि जांच अभी चल रही है और रिपोर्ट पूरी होते ही आयोग को भेजी जाएगी। श्री सांपला ने बताया कि प्रदेश सरकार से मीडिया के एक हिस्से में आई उन खबरों को लेकर भी सफाई मांगी गई है, जिनके अनुसार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संबद्ध विभाग के मंत्री को क्लीन चिट दी थी। सरकार से पूछा गया है कि यदि जांच पूरी नहीं हुई तो क्लीन चिट कैसे दी गई। उन्होंने बताया कि आयोग ने प्रदेश सरकार को जो समय दिया था अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए पूरा हो चुका है इसलिए आयोग अब फिर सरकार को लिखेगा और रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के लिए कहेगा। उन्होंने बताया कि आयोग ने पंजाब सरकार से पीपीएस से लेकर आईपीएस की पदोन्नति व न्यायपालिका में जाने वाले पीसीएस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों की भर्ती में आरक्षण नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है।

योजना *शिक्षा पर सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान*

प्रदेश में ढाई वर्ष में 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए : गहलोत

जयपुर, 8 अगस्त (एजेंसियां)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा का बेहतरीन माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है तथा गत मात्र ढाई वर्ष में ही 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं ताकि युवाओं को उनके गांव के नजदीक ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके। श्री गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जय मीनेष आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर, कोटा के शिलान्यास तथा आदिवासी मीना बालिका छात्रावास, प्रतापनगर, जयपुर के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के साथ ही अन्य वर्गों में शिक्षा के प्रसार की दिशा में अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति,

इस कदम से युवाओं का शैक्षिक और सामाजिक विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पिछली सरकार के समय वर्ष 2013 में नगर विकास न्यास कोटा ने रियायती दर पर 30 एकड़ भूमि इस विश्वविद्यालय के लिए आवंटित की थी। यह खुशी की बात है कि 15 करोड़ की लागत से बनने वाले इस विश्वविद्यालय के भवन का आज शिलान्यास हुआ है। आशा है कि जल्द ही यह काम पूरा होगा और यहां शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होंगी। इसी तरह जयपुर में 3000 वर्ग मीटर भूखण्ड पर बने आदिवासी मीना बालिका छात्रावास का फायदा प्रतिभावान बालिकाओं को मिल सकेगा।

श्री गहलोत ने कहा कि जरूरतमंद वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल की तैयारी के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना लागू की है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने बजट में घोषणा की है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं होने पर उस विद्यालय को कन्या महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्राओं के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कटी योजना की संख्या प्रतिवर्ष 2500 से बढ़ाकर 10 हजार से अधिक कर दी गई है। साथ ही दिव्यांगों को भी स्कूटी दी जाएगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष करीब 13 हजार स्कूटियों का वितरण होगा।

श्री गहलोत ने इस दौरान संस्था के जयपुर और कोटा छात्रावासों में रह रहीं छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने इन बालिकाओं के आत्मविश्वास को सराहा और हौसला अफजाई की। नर्सिंग छात्रा निकिता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही चिंता मीना और मधुबाला ने छात्रावास के अपने अनुभव बताए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं के साथ-साथ संस्था के सहयोग से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

इस अवसपर पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कोटा एवं जयपुर में बालिका छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। उनका लाभ बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवेश से आई छात्राओं को मिल रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कोटा में जय मीनेष विश्वविद्यालय स्थापित करने का जो बीड़ा संस्था ने उठाया है, वह समयबद्ध रूप से

श्रावण अष्टमी नवरात्र के दौरान हिमाचल में प्रवेश के लिए टीकाकरण, कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी

शिमला, 8 अगस्त (एजेंसियां)। सोमवार से शुरू हो रहे श्रावण अष्टमी नवरात्र के लिए हिमाचल प्रदेश में श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में प्रवेश की संभावना देखते हुए प्रदेश में प्रवेश के लिए टीके के दोनों डोज़ लगे होना अथवा 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह दिशानिर्देश जारी किये हैं। नौ अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलने वाले श्रावण अष्टमी नवरात्र के दौरान आसपास के प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहां के मंदिरों में आने की संभावना होती है। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार अलावा मंदिरों व धर्म स्थलों में

शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए, जिससे कोई आहत नहीं हो

मुख्यमंत्री ने असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह के विमोचन कार्यक्रम को किया संबोधित

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी संस्कृति, संस्कार, जीवन मूल्य और शिष्टता यह कहती है कि शब्दों का उचित चयन होना आवश्यक है। संसद तथा विधानसभा में विभिन्न विषयों को प्रस्तुत करते समय कभी-कभी क्रोध, आवेश या आक्रोश में ऐसे शब्द निकल जाते हैं, जो सामान्य शिष्टाचार की परिधि के बाहर होते हैं। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए, जिससे कोई आहत न हो।

मुख्यमंत्री चौहान विधानसभा सचिवालय द्वारा तैयार की गई पुस्तक असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह के विमोचन अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा स्थित मानसरोवर सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ, गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा तथा पूर्व संसदीय कार्य मंत्री व प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक डॉ.गोविंद सिंह समेत मध्यप्रदेश शासन के अनेक मंत्रीगण, सदस्यगण एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद और विधानसभा प्रजातंत्र के मंदिर हैं। यहां सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्रजीत गुप्त, सोमनाथ चटर्जी जैसे सांसदों की समृद्ध परम्परा रही है। मप्र विधानसभा में भी वरिष्ठ और अनुभवी वक्ताओं के वक्तव्य हुए हैं। मप्र विधानसभा द्वारा असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह पुस्तक का प्रकाशन अभिनंदनीय प्रयास है। इससे विधायकों और सदन की गरिमा बढ़ेगी। यह पुस्तक सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

बनी रहे प्रजातंत्र की पहचान : कमलनाथ

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि संसदीय शब्दावली पर पुस्तक तैयार की गई है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले महापुरुषों का स्वपन था कि भारत में ऐसे प्रजांतत्र की स्थापना हो जो संपूर्ण विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत करे। आज भारत की महानता उसके प्रजातंत्र से पहचानी जाती है। हमारी संसदीय परंपरा की अपनी एक पहचान है, इसलिए सभी सदस्यों को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे प्रजातंत्र की यह पहचान बनी रहे। स्वागत उद्बोधन विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने दिया। मुख्य सचेतक एवं पूर्व मंत्री डा. गोविंद सिंह ने आभार व्यक्त किया।

लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी सदस्यों की : गौतम

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है तो इस मंदिर की गरिमा बनी रहे, जनता की आस्था इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति प्रगाढ़ हो इसकी जिम्मेदारी भी हम सभी सदस्यों की ही है। हम सभी को यह प्रयास करना है कि आवेश, गुस्से या किसी भी परिस्थिति में माननीय सदस्य ऐसे शब्द का प्रयोग सदन में नहीं करेंगे जो असंसदीय हैं। विधानसभा सचिवालय ने अब तक सदन में जिन शब्दों को विलोपित किया गया है उसकी पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सभी माननीय सदस्य गंभीर एवं प्रदेश के विकास के प्रति समर्पित हैं। वे चुनाव जीत कर जनता के समर्थन से यहां पहुंचे हैं। आप जनता के नायक हैं, इसलिए ऐसा व्यवहार ही करें कि आपकी नायक की छवि में और सुधार हो।

मिस्टर बंटाधार सहित लगभग 1500 शब्द और वाक्यों का उपयोग अब सदन में नहीं होगा

विस सचिवालय ने असंसदीय शब्द की श्रेणी में डाला

भोपाल (एजेंसी)। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान यदि किसी शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वह था मिस्टर बंटाधार। यह शब्द इतनी चर्चा में आया कि यह मौजूदा सत्ताधारी दल भाजपा के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुआ। यह शब्द 2003 के विधानसभा चुनाव के समय आम से लेकर खास लोगों की जुबां पर चढ़ गया था। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पतन और भाजपा के उदय का यह सबसे बड़ा माध्यम बना। 2003 को गुजरे हुए 18 साल हो गए, लेकिन इस शब्द ने पीछा नहीं छोड़ा। विधानसभा का शायद ही कोई ऐसा सत्र हो, जिसमें विधायक सदन के अंदर इस शब्द का उपयोग नहीं करते रहे हों, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। विधानसभा के सोमवार से शुरू होने वाले सत्र के दौरान अब कभी भी मिस्टर बंटाधार का उपयोग सदस्य नहीं कर सकेंगे। यह इसलिए कि विधानसभा सचिवालय ने इस शब्द को असंसदीय शब्द की श्रेणी में डाल दिया है। अब सदन में इस शब्द का जिक्र करना विधानसभा आचरण नियमावली का उल्लंघन होगा।

दिग्विजय सिंह के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल होता रहा मिस्टर बंटाधार

विधानसभा सचिवालय ने रविवारको असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह जारी किया। इसमें लगभग 1500 असंसदीय शब्द और वाक्यांश को असंसदीय की श्रेणी में डाला गया है। यानी अब जब भी सदन में सदस्य चर्चा में हिस्सा लेंगे, तो इस तरह के शब्द और वाक्यों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अब मिस्टर बंटाधार शब्द सदन के चर्चा से पूरी तरह विलोपित हो जाएगा। यहां बता दें कि वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान तब के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने मिस्टर बंटाधार के नाम से बाकायदा एक पुस्तिका जारी की थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मुख्य पृष्ठ पर एक कार्टून छापा गया था और अंदर के पन्नों में उनके कार्यकाल की असफलताओं का सिलसिलेवार जिक्र किया गया था। तब इसकी चर्चा पूरे प्रदेश और देश में हुई थी। तब से लेकर अब तक भाजपा सरकार के चार कार्यकाल के दौरान सदन में मिस्टर बंटाधार का जिक्र हो ही जाता था। यह शब्द एक अराजक और असफल नेता की पहचान बन गया था, लेकिन अब भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही मिस्टर बंटाधार शब्द को असंसदीय की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसके साथ ही मिस्टर बंटाधार का युग भूल गए, के वाक्य को भी असंसदीय की श्रेणी में माना गया है। इससे अब संभावना बनी है कि दिग्विजय सिंह के लिए उपयोग किए जाने वाले इस शब्द से अब भाजपा सरकार ही उनको मुक्ति दिला देगी।

इस तरह के शब्द भी असंसदीय

झूठ, उल्लू का पट्ठा, सफेद झूठ, मूर्ख, बेईमान, मुर्खतापूर्ण, अन्याय, निकम्मे, नालायकी, चोर, पागल, बूढ़ा शेर, बकवास, बदमाश, हरामखोर, उचक्का, गुण्डा, पोस्टमैन, टुच्चा, ढोंगी, पाखंडी, चुड़ैल, फासिस्ट, हिस्ट्री शीटर, निठल्ले, धिक्कार, गुलाम, चमचे, चाटुकारिता, मक्कारी, चारण, यार, शेम, मख्ख्र बाजी, ढपोलशंखी आदि।

1954 से लेकर पिछले सत्र तक के शब्द हटाए, बीच में 14 वर्ष के शब्दों का नहीं किया जिक्र: असंसदीय शब्दावली में 23 सितंबर 1954 को सदन में उपयोग किए गए असंसदीय शब्द ससुर और गंदी सूरत का जिक्र किया गया है। तब से लेकर पिछले विधानसभा सत्र में उपयोग किए गए असंसदीय शब्द को संग्रह में शामिल किया गया है, लेकिन 24 जनवरी 1990 से लेकर 11 जनवरी 2014 से पहले हुए विधानसभा सत्र के दौरान उपयोग किए गए असंसदीय शब्दों का जिक्र नहीं किया गया है। इस तरह लगभग 14 वर्ष की अवधि के सत्र का जिक्र नहीं किया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले कृषि मंत्री कमल पटेल

भोपाल । प्रदेश के कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य मुलाकात की। श्री पटेल ने बताया कि उन्होंने मध्यप्रदेश में वर्तमान में अतिवृष्टि और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से श्री सिंह को अवगत कराया। श्री पटेल ने संकट की इस घड़ी में भारतीय सेना के द्वारा निरंतर दिए गए सहयोग के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कृतज्ञता व्यक्त की।

कांग्रेसजन बाढ़ पीड़ितों की हरसंभव मदद करें : यादव

भोपाल । ।प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के कई जिलों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ जैसे गंभीर हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रदेश सरकार से बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत देने की मांग की है। इसी संबंध में मप्र कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव ने सहकारिता प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ताओं एवं कांग्रेसजनों से अपील की है कि जिला दतिया में लांच-इंदरगढ़-पिछोर एवं रतनगढ़ वाली माता का पुल, सेवढ़ा का पुल तथा जिला शिवपुरी में भगरौली पुल, जिला श्योपुर में सीप नदी पुल, मानपुर गिरवर पुर मार्ग पर बना पुल, सोनभद्र का पुल, सिंध पुल ओरई-अडोखर मार्ग पुल के ढह जाने से आस-पास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पूर्व मंत्री श्री यादव ने सहकारिता क्षेत्र के सभी साथियों एवं कांग्रेसजनों से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य चलाकर पीड़ित परिवारों की हरसंभव मदद उपलब्ध कराने की अपील की है।

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई थी बैठक

सर्वदलीय बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग पर अड़ी कांग्रेस

भोपाल (एजेंसी)।

विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई।

बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में विधायी कार्य के सुचारू संचालन में सभी दलों का सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि सदन में सभी दलों के सदस्यों का आचरण ऐसा हो कि वह दूसरों के लिए मिसाल बने। इस दौरान दोनों ही प्रमुख दलों ने अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि वे पूरा सहयोग करेंगे। इस बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मानसून सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए। वे सदन की अवधि को बढ़ाने की मांग पर अड़ गए। वे प्रदेश में चर्चा के लिए कई महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय होने का जिक्र करते हुए कहा कि इतने कम समय में चर्चा संभव नहीं है। सत्ताधारी दल को सदन में चर्चा से भागना नहीं चाहिए। बैठक में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने पहले ही सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए राज्यपाल को भी पत्र लिखा है। आज हम विधानसभा अध्यक्ष से भी अनुरोध करते हैं कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, जिससे कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सके।

सदन में यह मुद्दे उठाएगा विपक्ष

मिले संकेतों के मुताबिक इस बार सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से उपजे हालात, इलाज के अभाव में मौतों के मामलों को प्रमुखता से उठाएगी। इसके अलावा मंदसौर में प्रदेश के वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री के गृह क्षेत्र में ही जहरीला शराब के सेवन से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत और हाल ही में बारिश और बाढ़ के हालात में प्रभावितों को समय पर भोजन तक का इंतजाम नहीं कर पाने सहित अन्य अव्यवस्थाओं के मामलों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य डॉ. गोविंद सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने भी हिस्सा लिया।

हवा से जनता की सेवा नहीं होती, यह कांग्रेस को समझना चाहिए

सिंधिया ने कसा कमलनाथ पर तंज

भोपाल (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जनता की सेवा जमीन पर रह कर एवं गांव-गांव जाकर की जाती है, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ हवा में ही रहने की आदत है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भाजपा सरकार को झूठ की सरकार बताने के बयान पर सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा कि हवा में रहकर जनता की सेवा नहीं की जाती, यह कांग्रेस नेताओं को समझ लेना चाहिए।

सिंधिया ने रविवार को यहां मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 15 माह कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इन 15 महीनों में कांग्रेस नेताओं ने अपने अलावा जनता की कभी सोच नहीं रखी, अब ऐसे में उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। जनता के बीच जाना नहीं चाहते, सेवा करने से दूर भागते हैं तो ऐसे नेता सिर्फ हवा से ही नजारा देखेगें। भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता एवं नेता सामूहिक रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो में जाकर जनता की सेवा करने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अंचल के सभी जिलों में दौरा कर चुके हैं और उन्होंने राहत के लिए हरसंभव मदद देने का भी भरोसा दिया है।

सिंधिया ने बताया कि आपदा कल्पना से परे है, हममें से किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि बाढ़ इस पैमाने पर आएगी, इस बाढ़ में जितनी हानि हुई है उसको बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि मैंने जो दृष्य देखा है वह काफी भयावह वाला है। केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर आपदा से प्रभावित लोगों की सेवा में लगी हुई हैं, हजारो लोगों की जान भी बचाई गई। सिंधिया ने बताया कि अभी भी खतरा टला नहीं है, इसलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बांधों में ऊपरी स्तर तक पानी भरा है और बारिश की संभावना बनी हुई है।

प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री लगातार ले रहे राहत कार्यों की जानकारी

सिंधिया ने बताया कि वे पिछले एक सप्ताह से रोजाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से राहत कार्यों को लेकर निरंतर चर्चा कर रहे हैं। शनिवार को भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ग्वालियर चंबल संभाग में 40 साल बाद आई इस प्राकृतिक विपदा को लेकर चर्चा की और राहत कार्यों की प्रगति के बारे में उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस भीषण आपदा में प्रदेश की आपदा प्रबंधन की सेवाएं पर्याप्त नहीं थी, इसलिए सेना एनडीआरएफऔर 6 हेलीकॉप्टर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगाए गए थे। हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने की वजह से दो दिन बाद राहत कार्यों में जुट सके। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिगड़े हुए मौसम को लेकर एक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए, जिससे किसी प्राकृतिक आपदा से लोगों को समय रहते सचेत किया जा सके और प्रशासन भी ऐसे में लोगों की सहायता कर सके। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि स्थानीय लोगों की मदद और संसाधनों से अभी तक करीब 20 हजार लोगों की जान बचाई जा सकी है। उनकी पहल है कि इस आपदा में जान, माल, पुल, सड़क का भारी नुकसान हुआ है। लोगों को हुए नुकसान का जल्द से जल्द आकलन करके राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

एसटी वर्ग के विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले कमलनाथ

आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने सहित अन्य मुद्दों पर की चर्चा

भोपाल (एजेंसी)। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को राज्यपाल मंगुभाई पटेल से कांग्रेस के एसटी वर्ग के विधायकों के साथ राजभवन पहुंचकर आदिवासी वर्ग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जिसमें आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का मामला प्रमुख है।

कांग्रेस मुख्यालय के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्यपाल से मांग की है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जावे। हमारी सरकार में हमने अवकाश भी घोषित किया था और हर ब्लॉक में इस दिवस को मनाने के लिए राशि भी दी थी। कई जिलों में धारा 144 लगाकर इस दिवस को मनाने से रोकने का काम शिवराज सरकार में किया जा रहा है। मेडिकल कालेज में आदिवासी वर्ग के बेकलाग के पद पर अन्य वर्ग के लोगों की भर्ती की जा रही है। नेमावर हत्याकांड की सीबीआई जांच हो और खंडवा सहित कई जिलो में आदिवासी वर्ग के मकान तोड़े जा रहे है। वनाधिकार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। गौरतलब है कि पहले भी कमलनाथ ने आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने को राज्यपाल को पत्र लिखा था।

प्रदेश सरकार ने आदिवासी वर्ग के साथ कुठाराघात कर निरस्त किया अवकाश

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार के समय विश्व आदिवासी दिवस पर इसे उत्सवपूर्ण बनाने के उद्देश्य से 9 अगस्त को अवकाश की घोषणा की थी, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार ने आदिवासी वर्ग के साथ कुठाराघात कर अवकाश पर विराम लगा दिया। कमलनाथ ने बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में पहले भी राज्यपाल को पत्र लिखकर 9 अगस्त अवकाश घोषित करने की मांग की थी। नाथ ने प्रदेश के नागरिकों को संदेश देते हुए कहा कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आदिवासी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक हितों की न केवल संरक्षक रही, बल्कि उनके उत्थान और आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए हरसंभव कार्य योजनाएं भी कांग्रेस की सरकारों के समय संचालित की गई, जिससे उनके विकास की नई इबारत लिखी गई। इसलिए आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाए। नाथ ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण ध्यान रखते हुए 9 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी छात्रावास के विद्यार्थियों, आदिवासी वर्ग के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क कर उनका मनोबल बढ़ाएं। कमलनाथ ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

विस अध्यक्ष के लिए आसान नहीं होगा असंसदीय शब्दों का उपयोग रोकना

भोपाल (एजेंसी)।

लंबी प्रतीक्षा के बाद विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को आखिरकार असंसदीय शब्द और वाक्यों की सूची जारी कर दी, जिसका उपयोग सदन में चर्चा के दौरान सदस्य नहीं कर सकेंगे। इस सूची की लंबे समय से प्रतीक्षा थी। कमोबेश दोनों ही दलों को इसका इंतजार था। आखिरकार शब्दों के बाण जब चलते हैं, तो फिर उससे घायल होने की आशंका बनी रहती है। कई बार ऐसे असंसदीय शब्द सदन में कड़वाहट घोल जाते हैं और कई बार सदन में गर्माहट का कारण भी बन जाते हैं। अब सूची जारी होने के बाद इसमें लगाम लगने की संभावना बन गई है। संभावना इसलिए कि वर्षों से सदन में इस तरह के असंसदीय शब्दों और वाक्यों का उपयोग करने वाले सदस्यों के लिए एकाएक पूरी तरह से संसदीय शब्दावली का उपयोग करना आसान नहीं होगा। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की सदन में कड़ी परीक्षा होगी। आखिरकार ऐसे शब्दों का उपयोग माननीय सदस्य सदन में नहीं करें, इस पर नियंत्रण करना उनके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। वैसे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। आखिर उनकी ही पहल पर असंसदीय शब्दों को छांटकर अलग करने और फिर पुस्तिका जारी करने का काम पूरा हुआ। वैसे तो मप्र विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है। प्रायः यहां संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखा गया है, लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति भी बन ही जाती है, जब संसदीय मर्यादाएं तार-तार हो जाती है। सदस्य संसदीय मर्यादा भूल जाते हैं। ऐसे में सदन के सुचारू संचालन के लिए नियमों का चाबुक भी चलाना होता है। वैसे भी अब समाज में ही नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। आचरण और व्यवहार में लोक-लिहाज का ध्यान रखना सबके बस की बात नहीं रह गई है। सोशल मीडिया और सूचना क्रांति के इस दौर में इस तरह के आचरण के मामले दिख जाते हैं। आखिरकार विधायक भी तो उसी समाज का हिस्सा है, जिसके नैतिक मूल्यों का लगातार क्षरण हो रहा है। ऐसे में मप्र के विधानसभा की गौरवशाली परंपरा को और आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए।

बीजेपी प्रशिक्षण कार्यक्रमः स्वास्थ्य स्वयंसेवकों से पार्टी नेताओं ने किया तैयार रहने का आह्वान

भाजपा ही एकमात्र दल, जिसने समाज सेवा के प्रतिमान गढ़े

भोपाल (एजेंसी)। हम ऐसे राजनीतिक दल के सदस्य हैं, जिसने समाज सेवा के नए प्रतिमान गढ़े हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर कोरोना की पहली और दूसरी लहर में खुद के जीवन को खतरे में डालकर लोगों की सेवा की। उन्हें भोजन, दवाएं, राशन और यहां तक कि अस्पताल में बेड तथा ऑक्सीजन तक दिलाने के प्रयास किए।

बीजेपी नेताओं ने जब हर बूथ को वैक्सीनेशन युक्त बनाने का आह्वान किया, तो हमारे कार्यकर्ता समर्पित होकर उसमें जुट गए। अब हमें कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने और उससे दो-दो हाथ करने के लिए तैयार रहना है। हमारी ये लड़ाई मानवता को बचाने के लिए है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महामारी के खिलाफ यह लड़ाई भी जीतेंगे। वो भाजपा जो सबसे अधिक सदस्यों, सांसदों, विधायकों वाली पार्टी है, वो अब सबसे बड़ी हेल्थ फोर्स बनाएगी। यह बातें जिला स्तरीय स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने कही। इस अवसर पर संगठन महामंत्री सुहास भगत, प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी मंचासीन थे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के प्रदेश संयोजक, प्रदेश महामंत्री सरतेंदु तिवारी ने प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत की।

31 अगस्त को हर मंडल में दी जाएगी ट्रेनिंग : चुघ

श्री चुघ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि 31 अगस्त को हर मंडल तक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस महीने सरकार ने 25 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है, इसी तरह अक्टूबर से 28 करोड़, नवंबर में 28.5 करोड़, दिसंबर में 28.5 करोड़ वैक्सीन लगेगी। 31 दिसंबर तक 135 करोड़ वैक्सीन स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच जाएगी।

अद्भुत है यह प्रशिक्षणः शिवराज सिंह-मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रशिक्षण राजनीतिक इतिहास में अद्भुत है और सेवा व सामाजिक परिवर्तन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यहां कोरोना से बचाव और उसके नियंत्रण के बारे में प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, जो जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए काम करेंगे।

हमें जनता और सरकार के बीच करना है सेतु का कामः शर्मा-प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए सरकार ने जो व्यवस्थाएं जुटाई हैं, उसमे भाजपा कार्यकर्ता भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएंगे। हमें जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करना है। इसके लिए जिला, मंडल और बूथ स्तर तक प्रशिक्षित स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैनात होंगे। कार्यक्रम के पूर्व प्रशिक्षण में मौजूद सभी अतिथियों एवं जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने ओलंपिक में भारत के स्वर्ण पदक जीतने पर भारत माता के जयकारे लगाए और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा

हम सदन में प्रमुखता से उठाएंगे जनहित के सारे मुद्दे

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने विधानसभा का सत्र जानबूझकर कम समय के लिए बुलाया है। जनहित के कई मुद्दे हैं ,सरकार जिससे बचना चाहती है। हम प्रमुखता से विधानसभा में जनहित के सारे मुद्दों को इस सत्र में उठाएंगे ,जनता की लड़ाई लड़ेंगे ,पूरी ताकत से लड़ेंगे ,सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने ग्वालियर-चंबल संभाग के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर कई प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान मैंने जो स्थिति देखी वह बेहद भयावह है। इन क्षेत्रों में बाढ़ से भारी तबाही हुई है, लोगों के पास खाने तक को नहीं है। बाढ़ में उनका सब कुछ इस बाढ़ में बह चुका है। अभी तक सरकार की कोई राहत इन प्रभावितों तक नहीं पहुंची है और राहत के नाम पर अभी तक शिवराज सरकार से सिर्फ घोषणाएं ही मिली हैं। जब मौसम विभाग भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी दी थी उसके बाद भी सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के कोई इंतजाम नहीं किए। जिसके कारण इस क्षेत्र में भारी बर्बादी हुई है, इन सब की जांच होना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि सरकार सिर्फ बाढ़ रेसक्यू के बढ़-चढ़कर आंकड़े बताने में लगी हुई है। सरकार की सोच व नजरिए में खोट है। उन्होंने कहा कि दो वर्ष बाद चुनाव हैं, सभी जुट जाएं,समय कम बचा है और जनता कांग्रेस को आशा व उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। जनता महंगाई से परेशान हैं। शिवराज सरकार के कोरोना में कुप्रबंधन और नाकारापन के कारण हजारों लोगों की मौत हुई ,यह हम सभी ने देखा है। हमें राजनीति के परिवर्तन को समझना होगा ,जिसका जनता से सीधा जुड़ाव होगा वही जनता का प्रिय होगा। हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं उसके संगठन से है। अपने-अपने क्षेत्रों में मंडलम-सेक्टर की मजबूती के लिए आप सभी जुट जाएं, दमोह उपचुनाव की जीत मंडल,सेक्टर की जीत है,संगठन की जीत है। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश के सहप्रभारी सुधांशु त्रिपाठी भी उपस्थित थे। बैठक को पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ,पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ,पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ,पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ,पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित कई विधायकों ने भी संबोधित किया।

द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2

महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है-शरद केलकर

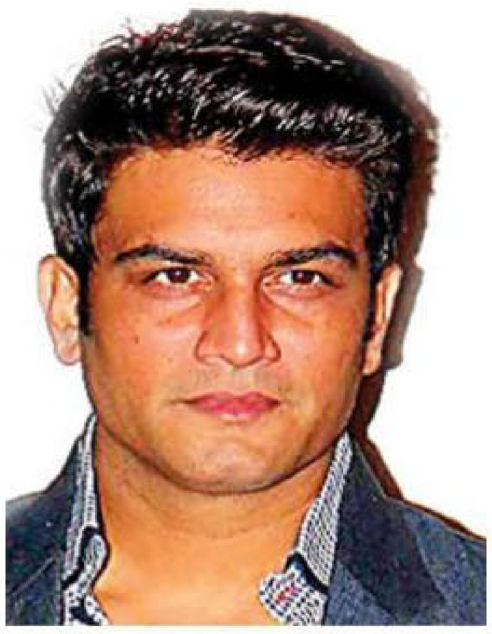

शरद केलकर एनीमेशन श्रृंखला द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2 के लिए कथाकार के रूप में लौट रहे हैं। अभिनेता का कहना है कि शो का यह सीजन दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है। उसी के बारे में बात करते हुए, शरद ने कहा, द लीजेंड ऑफ हनुमान के पहले सीजन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और डिजिटल सामग्री के लिए एक मील का पत्थर बन गया। पौराणिक कथा हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। इन पौराणिक कथाओं को सभी उम्र के दर्शकों के सामने दिखाने का ये एक अद्भुत माध्यम। उन्होंने आगे कहा कि मैं द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2 की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जो कि सबसे बड़ी बुराई का सामना करने पर सबसे शक्तिशाली योद्धा कैसे अपनी शक्तियों को गले लगाता है, इसकी प्रेरक कहानी दिखाता है। ये अच्छाई का रास्ता दिखाएगा जो सभी को पसंद आएगा। नवीनतम सीजन महाबली हनुमान की यात्रा को आगे ले जाता है क्योंकि शक्तिशाली योद्धा रावण और उसकी सेना का सामना करता है। शरद देवराजन, जीवन जे. कांग और चारुवी पी. सिंघल द्वारा निर्मित द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2 का निर्देशन कांग और नवीन जॉन ने किया है, जिसमें देवराजन, सरवत चड्ढा, अश्विन पांडे और अरशद सैयद प्रमुख लेखक हैं। 13-एपिसोड श्रृंखला हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयालम और कन्नड़ में उपलब्ध होगी और 6 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी।

निर्माता विभु अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप

फिल्म निर्माता विभु अग्रवाल के खिलाफ हाल ही में मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया है। विभु पर महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 के तहत यह केस दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विभु के अलावा कंपनी की कंट्री हेड अंजली रैना पर भी केस दर्ज किया गया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने कहा-पुलिस ने फिल्म निर्माण कंपनी उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ विभु अग्रवाल के खिलाफ मुंबई में आईपीसी की धारा 354 के तहत एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया है। विभु अग्रवाल के साथ ही उनकी कंपनी की कंट्री हेड अंजलि रैना पर भी मामला दर्ज किया है। उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विभु की अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। यह कंपनी एडल्ट कंटेंट बनाने के लिए जानी जाती है। 2013 में विभु अग्रवाल ने बॉलीवुड फिल्म बात बन गई प्रोड्यूस की थी। खबरों की मानें तो इस मामले में विभु अग्रवाल को गिरफ्तार भी किया गया है हालांकि गिरफ्तारी की बात की कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं हैं तो हम इस पर किसी प्रकार की पुष्टि नहीं कर रहे हैं लेकिन मुंबई पुलिस ने मामला गंभीरा धारा के तहत दर्ज कर लिया है। साफ है कि विधु की परेशानी भी इससे अब काफी बढ़ने वाली हैं। 2018 में उन्होंने उल्लू एप लॉन्च किया था। इस पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भोजपुरी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और गुजराती भाषा में भी कार्यक्रम स्ट्रीम होते हैं। बी-टाउन इंडस्ट्री से लगातार महिलाओं पर हुए कथित अत्याचार की खबरें आ रही हैं। महिलाओं के साथ रेप, पत्नी के साथ मारपीट मामले सामने आने के बाद इंडस्ट्री एक बार फिर कटघड़े में हैं।

शर्लिन चोपड़ा से पूछताछ करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच, भेजा समन

अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें एप पर अपलोड करने के आरोप में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं। मुंबई पुलिस लगातार राज कुंद्रा के खिलाफ सबुत जुटाने में लगी हुई है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को भी समन भेजा है। बताया जा रहा है कि शर्लिन चोपड़ा से क्राइम ब्रांच की टीम आज यानि 6 अगस्त को पूछताछ करेगी। बीते दिनों शर्लिन ने राज कुंद्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। खबरों के अनुसार शर्लिन चोपड़ा ने महाराष्ट्र साइबल सेल को स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले राज कुंद्रा हैं। शर्लिन को प्रति प्रोजेक्ट 30 लाख रुपये दिए जाते थे।

ओलंपिक में हार के बाद

शाहरुख ने बढ़ाया महिला हॉकी टीम का हौसला

टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को ग्रेट ब्रिटेन से हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट कर रही थी। लेकिन इस हार के बाद भी महिला हॉकी टीम के पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने पर हर कोई तारीफ कर रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी हॉकी टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। शाहरुख ने ट्वीट किया, दिल टूट गया! लेकिन आप सभी ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अच्छा खेला। आप सभी ने पूरे भारत को प्रेरित किया, ये अपने आप में बड़ी जीत है। शाहरुख खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस ट्वीट पर कमेंट करके हर कोई भारतीय महिला हॉकी टीम की तारीफ कर रहा है। शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह इन दिनों फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में वह दीपिका पादुकोण के साथ नजर आएंगे। फिल्म में जॉन अब्राहम विलेन का रोल निभाने वाले हैं।

माता-पिता के तलाक पर सारा अली खान बोलीं

जब रिश्ता दर्द बन जाए तो उसे छोड़ देना ही...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। सारा फैंस के साथ अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात करती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में सारा अली खान ने एक इंटरव्यू में अपने परेंट्स के तलाक पर बाती की। सारा अली खान जल्द ही वूट के शो फीट अप विद द स्टार्स के सीजन 3 में नजर आने वाली हैं। इस दौरान वह अपने पिता सैफ अली खान और मां अमृता सिंह के रिलेशनशिप के बारे में बात करती नजर आएंगी। इस शो से जुड़ा एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब सारा अली खान से पूछा गया कि उनके मम्मी-पापा का तलाक हुआ तब उन्हें कैसी-कैसी चीजों का सामना करना पड़ा? इस पर सारा ने कहा कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो वक्त अच्छा था लेकिन ओवरऑल आज देखा जाए तो ये कह सकती हूं कि जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा, आज मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी-पापा अपनी-अपनी दुनिया में खुश हैं। मेरा मानना है कि अगर आप साथ रहें लेकिन खुश ना रहें तो जिंदगी काफी बोझिल हो जाती है। ऐसे में बेहतर है कि आप अलग ही हो जाएं और खुश रहें। जब रिश्ता दर्द बन जाए और दुख देने लगे तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सारा ने कहा, तलाक के बाद मैं अपनी मां के साथ रहती हूं और वह मेरी बेस्टफ्रेंड हैं लेकिम मेरे पापा हमेशा मेरे लिए मौजूद होते हैं। आज दोनों लोग अपनी-अपनी दुनिया में काफी आगे निकल चुके हैं। मुझे यही लगता है कि दोनों का अलग हो जाना एक सही फैसला था। बता दें कि सैफ ने अमृता से 1991 में विवाह किया था। एक बेटा और एक बेटी होने के बाद 2004 में दोनों के बीच तलाक हो गया। 2012 में सैफ ने करीना कपूर से दूसरी शादी की। सैफ-करीना के दो बेटे हैं।

जयेशभाई जोरदार की अभिनेत्री शालिनी पांडे ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर किया खुलासा

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म जयेशभाई जोरदार से बॉलीवुड में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार शालिनी पांडे का कहना है कि उन्हें हमेशा अपनी फीजिक पर भरोसा रहा है और उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या कह रहे है। अर्जुन रेड्डी में अपने अभिनय से प्रसिद्धि पाने वाली शालिनी का कहना है कि उन्होंने कभी भी उद्योग के लिए एक निश्चित रास्ता देखने का दबाव महसूस नहीं किया। उसने कहा कि मुझे हमेशा से अपनी फीजिक पर भरोसा रहा है और मैंने वास्तव में इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं शारीरिक रूप से जिस भी चरण में थी, उससे प्यार करती थी और वास्तव में एक निश्चित शरीर के प्रकार के लिए खुद पर दबाव नहीं डालती थी। वह मानती हैं कि महिलाओं की बेवजह स्क्रूटनी की जाती है कि वे कैसी दिखती हैं। शालिनी ने कहा कि मुझे लगता है कि शारीरिक रूप से एक निश्चित तरीके से महिलाओं पर बहुत दबाव होता है और यह सही नहीं है। इसलिए, मैं वास्तव में इसे एक परिवर्तन के रूप में नहीं देखती हूं। मैं इसे एक ऐसे चरण के रूप में देखती हूं जिसे मैंने कैसे हासिल किया है। हालांकि, मैं इस बात से खुश हूं कि मैं अभी जैसी दिख रही हूं और अपने दिमाग में भी अच्छा महसूस कर रही हूं। उन्होंने साझा किया कि वह जीवन भर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रही है। अपने वजन घटाने के बारे में बात करते हुए, शालिनी ने कहा कि वजन घटाने के लिए, मुझे एक भोजन योजना मिली और सौभाग्य से मैं एक ऐसी फिल्म कर रही थी जिसके लिए भारी मात्रा में डांस रिहर्सल की आवश्यकता थी जिससे मेरा वजन कम हुआ। ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो मैंने अपना वजन कम करने के लिए किया। लेकिन मुझे लगता है कि भोजन योजना वास्तव में अच्छी तरह से काम करती है। मैं रोजाना लगभग चार घंटे नृत्य कर रही थी और कार्डियो है जिसने मुझे बहुत मदद की। शालिनी अपनी फिल्म जयेशभाई जोरदार के बड़े पर्दे पर रिलीज होने को लेकर उत्साहित हैं। वह कहती हैं कि वह सिनेमाघरों में अपनी फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साहित हैं और उम्मीदों के दबाव को महसूस नहीं कर रही हैं। वहीं रणवीर ने जयेशभाई को चमत्कारिक स्क्रिप्ट कहा है।

Bigg Boss OTT में सबका लबर-लबर बंद करने आ रही हैं भोजपुरी ऐक्ट्रेस

'बिग बॉस ओटीटी' को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स सामने आ रहे हैं। अब शो में हिस्सा लेने वाली एक और कंटेस्टेंट का खुलासा हो गया। सामने आए प्रोमो में कंटेस्टेंट अपने पूरे स्वैग में नजर आ रही हैं।

-शो की नई कंटेस्टेंट का वीडियो

भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह 'बिग बॉस ओटीटी' में हिस्सा लेने वाली हैं। प्रोमो से पहले यह जानकारी सामने आ चुकी थी कि अक्षरा 'बिग बॉस ओटीटी' में जाने वाली हैं। अब यह खबर पक्की हो चुकी है। हालांकि उनका चेहरा अभी भी साफ-साफ नहीं दिखाया गया है लेकिन जो उनके फैंस है उन्हें जरूर पहचान जाएंगे।

-अक्षरा सिंह दिखाएंगी दम

प्रोमो वीडियो में वह कहती हैं कि 'जो लोग हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खराब कर देते हैं ना, इन सबका लबर-लबर (बोलती) बंद कर देंगे। वैसे तो हम जबरदस्ती का रोमांस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहां जरूरत पड़ी ना तो हमको एक्शन भी बराबर करने आता है। अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की बड़ी स्टार हैं। वह पवन सिंह के साथ अफेयर की खबरों को लेकर चर्चा में रही हैं। बाद में दोनों के रिश्ते इस कदर खराब हो गए थे बात पुलिस तक पहुंच गई थी।

-करण जौहर का प्रोमो

'बिग बॉस ओटीटी' फिल्ममेकर करण जौहर होस्ट करने वाले हैं। एक प्रोमो के जरिए उन्होंने संकेत दे दिया है कि इस बार शो टीवी से कहीं ज्यादा बोल्ड होने वाला है। प्रोमो में करण कहते हैं, 'टीवी पर सलमान होस्ट करेंगे सूट में, बूट में और मैं होस्ट करूंगा बिग बॉस ओटीटी वूट में।

नरगिस फाखरी का छलका था दर्द

मॉडल और अभिनेत्री नरगिस फाखरी को फिल्म 'रॉकस्टार' के लिए जाना जाता है। नरगिस ने बॉलीवुड में कम ही फिल्में की हैं। वह अपने बेबाक बयान देने से नहीं चूकतीं। एक्ट्रेस कई बार सर्जरी की सलाह से लेकर कास्टिंग काउच पर खुलकर बात कर चुकी हैं। पूर्व पोर्न स्टार ब्रिटनी डी ला मोरा के साथ बातचीत करते हुए नरगिस फाखरी ने अपने करियर की मुश्किलों पर बात की थी। नरगिस ने कहा था कि 'मैं किसी चीज की भूखी हूं? मुझे प्रसिद्धि की भूख नहीं है कि मैं न्यूड पोज दे दूं या फिर कुछ अन्य चीजें या फिर निर्देशक के साथ सोऊं। मैंने कई मौके खो दिए क्योंकि कुछ चीजें मैंने नहीं कीं। यह दिल तोड़ने वाला है। मैं वहां टिके रहने की कोशिश कर रही हूं जहां मेरे हाई स्टैंडर्ड हैं। बहुत बुरा लगता है क्योंकि मुझे कई बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे मुझे दुख हुआ लेकिन मैं खुद से कहती रही कि जो लोग अपने मूल्यों पर टिकेंगे वहीं जीतेंगे। खुद के प्रति ईमानदार रही और किसी को मुझे किसी चीज के लिए मनाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए नैतिक मूलियों से ज्यादा कुछ नहीं है। नरगिस कहती हैं कि 'मैं खुश हूं कि मैं बॉलीवुड में हूं क्योंकि वे सेक्स सीन्स नहीं करते। मॉडलिंग के दिनों में कई बार टॉपलेस और नेकेड शॉट्स के लिए पूछा गया लेकिन मैं इन सब में कंफर्टेबल नहीं हूं। नरगिस की मुख्य फिल्मों 'मद्रास कैफे', 'किक' और 'हाउसफुल 3' हैं। आखिरी बार वह 2020 में संजय दत्त के साथ 'तोरबाज' में नजर आई थीं।

"मेरी भावना' दैनिक समाचार पत्र, स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः भावना वाधवानी द्वारा अलयौम प्रिंटिंग प्रैस 1534 गली कासिम जान बल्लीमारान दिल्ली-6, से मंद्रित करके।
K-1098 दूसरी मंजिल, जहांगीरपुरी दिल्ली-33, से प्रकाशित किया। संपादकः भावना वाधवानी E-mail: meri.bhawana@yahoo.com
इसके समस्त दीवानी विवादों, न्यायोचित कार्रवाईयों एवं दंडित परिवादो के लिए क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालय में रहेगा

कांस्य के लिए पहलवान बजरंग पुनिया ने घुटने की गंभीर चोट के बावजूद जोखिम उठाया

मुंबई, 8 अगस्त (आईएएनएस)7 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए पहलवान बजरंग पुनिया ने कजाखस्तान के दाउलेत नियाजबेकोव के साथ मुकाबला घुटने में दर्द के साथ खेला और गंभीर चोट का जोखिम उठाया। बजरंग ने ओलंपिक के पहले तीन बाउट, राउंड-16, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मुकाबले चोटिल घुटने के साथ खेला। शनिवार को, उन्होंने अपने कोचों की आपत्तियों को खारिज कर दिया और कजाख पहलवान के खिलाफ कांस्य पदक मैच के लिए सुरक्षा प्राप्त करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाए और वह पदक की दौड़ से बाहर हो जाएं।

बजरंग ने कहा, पदक जीतना जरूरी था। पहले तीन बाउट में मैंने घुटने को सुरक्षित किया। कांस्य पदक का मैच टोक्यो में मेरा आखिरी मुकाबला था और मैंने जोखिम उठाया। मैंने फिजियो को घुटने में स्ट्रैप करने नहीं दिया। वह खुश नहीं थे लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाए क्योंकि कांस्य पदक ज्यादा जरूरी था। बजरंग से पहले केडी जाधव (हेलसिंकी 1952), सुशील कुमार (बीजिंग 2008 और लंदन 2012), योगेश्वर दत्त (लंदन 2012) और साक्षी मलिक (रियो 2016) में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।

बजरंग भी ओलंपिक में पदक हासिल करने वालों की सूची में शामिल हो गए लेकिन उन्हें इसके लिए भारी जोखिम उठाया।

बजरंग के घुटने में पिछले महीने रूस में अली अलियेव मेमोरियल टूर्नामेंट के दौरान चोट लगी थी। ओलंपिक से पहले वह 20 दिनों तक मैच से दूर रहना पड़ा था। बजरंग ने कहा, मैट से 20-25 दिन दूर रहने से मेरी तैयारियों पर असर पड़ा। टोक्यो में मैं स्वतंत्र तरीके से बाउट में मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे घुटने को सुरक्षित करना पड़ रहा था। लेकिन अंतिम मैच में उनका ध्यान पदक जीतने पर था, इसलिए मैंने जोखिम लिया क्योंकि इसके बाद टोक्यो में मेरा कोई बाउट नहीं था। बजरंग ने कहा कि वह स्वदेश लौटने के तुरंत बाद पुनर्वसन में जाएंगे और बाद में अगले साल एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की योजना बनाने के लिए अपने कोचों और सहयोगी स्टाफ के साथ बैठेंगे।

भारत में अमेरिकी दूतावास ने ओलंपिक में भारत की सफलता का जश्न मनाया

नई दिल्ली, 8 अगस्त (एजेंसियां)। भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने रविवार को अपने ट्विटर पेज पर भारत के सात ओलंपिक पदक विजेताओं की फोटो पोस्ट की और संदेश लिखकर इनकी सफलताओं का जश्न मनाया। अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट कर लिखा, ओलंपिक दुनिया को खेल में एक साथ लाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन और अपनी सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका के लिए टीम इंडिया को बधाई। आप सभी सच्चे चैंपियन हैं। टीम इंडिया का जश्न मनाने के लिए हम आज अपने पेज पर टोक्यो 2020 के पदक विजेताओं को हाइलाइट कर रहे हैं। अमेरिका ने ओलंपिक में 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य सहित 113 पदक जीते जबकि भारत एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक सहित सात पदकों के साथ 48वें नंबर पर रही।

अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट कर लिखा, पीवी सिंधु ने दो ओलंपिक पदक जीत पहली भारतीय महिला एथलीट बनकर इतिहास रचा। भारोत्तोलक मीराबाई चानू के लिए दूतावास ने लिखा, मीराबाई ने ओलंपिक के पहले ही दिन रज पदक जीता और इतिहास रचा। व पहली भारतीय भारोत्तोलक जिन्होंने ओलंपिक में रजत पद जीता है। मीराबाई को बधाई, आ सच्ची प्रेरणास्रोत्र हैं।

भाला फेंक एथलीट और स्व पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा के लिए लिखा, ओलंपिक गोल्ड फॉ इंडिया। पानीपत के इस लड़के जश्न मनाने को गर्व करने क मौका दिया। दूतावास ने टोक्य ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के दि भारतीय दल के मार्च करते हुए क एक तस्वीर भी पोस्ट की।

एथलेटिक्स में बेहतर प्रदर्शन के लिए नए टेलेंट की तलाश जरूरी : पी.टी. ऊषा

तिरुवनंतपुरम, 8 अगस्त (एजेंसियां)। भारत की प्रसिद्ध एथलीट पी. टी. ऊषा का कहना है कि एथलेटिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नए टेलेंट की तलाश जरूरी है। ऊषा 1984 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही थीं और पदक लाने से मामूली अंतर से चूक गई थीं। ऊषा ने आईएएनएस से बात करते हुए नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने सहित अन्य विषयों पर अपनी राय रखी। साक्षात्कार के अंश इस प्रकार है।

- **नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रचा है। इस जीत पर आपकी क्या राय है?**

नीरज की जीत ने देश का मनोबल बढ़ाया है जिसने मामूली अंतर से एथलीटों को पदक से चूकते हुए देखा है। इससे यह एहसास होता है कि हम कर सकते हैं। यह इस देश के युवाओं और बच्चों के प्रदर्शन के लिए प्रेरणा है और मुझे लगता है कि भारत भविष्य में एथलेटिक्स में कई स्वर्ण पदक विजेता पैदा करेगा।

- **एक शीर्ष भारतीय एथलीट के रूप में, क्या आपको लगता था कि नीरज टोक्यो में इस तरह से प्रदर्शन करेंगे?**

मैंने उन्हें 2016 आईएएफ अंडर-20 विव चैंपियनशिप में थ्रो करते देखा था और उन्होंने 86.48 मीटर का थ्रो कर वहां स्वर्ण जीता था। विश्व चैंपियनशिप में प्रदर्शन करने वाले एक अंडर 20 वर्षीय एथलीट के रूप में, मैं उनके शांत आचरण और उनकी मानसिक शक्ति को देख सकती थी और मुझे पता था कि वह बड़ी चीजों के लिए बने हैं।

- **आपके अनुसार नीरज की ओलंपिक में जीत के क्या बड़े कारण हैं?**

मैंने पहले भी कहा है कि नीरज ऐसा एथलीट है जो ध्यान केंद्रित रखते हैं। वह कभी दबाव में नहीं आते जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में काफी मायने रखता है। हमारे पास कैसा भी टेलेंट हो लेकिन हम तब तक अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते जब तक ध्यान केंद्रित नहीं करें। अपनी प्रतिभा को निखारना और मानसिक रूप से शांत रहना जरूरी है और ये सभी गुण नीरज में दिखे।

- **यह भारतीय स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स के लिए बड़ा पल है। एक पूर्व एथलीट के नाते आपकी ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में ज्यादा स्वर्ण पदक लाने के लिए क्या राय है?**

हमें नए टेलेंट की खोज कर उन्हें महान एथलीट के रूप में विकसित करना होगा। मैंने कई वर्षो से यह सुझाव दिया है। हमें टेलेंट को ढूंढना होगा। हम अभी सिर्फ बेहतर करने वाले को प्राथमिकता देते हैं लेकिन नए टेलेंट की तलाश करना एकदम अलग है। ग्रामीण भारत में हमें ऐसे टेलेंट मिल सकते हैं।

- **एथलेटिक्स और खेलों को लेकर भारत सरकार की प्रतिक्रिया कैसी है?**

भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को लेकर काफी बेहतरीन काम किया है। प्रधानमंत्री की देखभाल और चिंता हम सभी ने देखी जब उन्होंने बेल्जियम से सेमीफाइनल में हार के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम को फोन किया और उन्हें बिना किसी तनाव के कांस्य के लिए खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। यह एक खिलाड़ी को अत्यधिक आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान देगा।

टोक्यो में अदिति के प्रदर्शन से गोल्फ में सकारात्मक बदलाव आएगा : लाहिड़ी

टोक्यो, 8 अगस्त (एजेंसियां)। शीर्ष भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेलों में पुरुषों की स्पर्धा में संयुक्त रूप से 42वां स्थान हासिल किया था, ने कहा है कि महिला गोल्फर अदिति अशोक का शनिवार को चौथे स्थान पर रहने का शानदार प्रयास एक नई उपलब्धि लेकर आया है और उनकी इस सफलता से इस खेल के बारे में लोगों के रवैये में बदलाव होना तय है।। भारत ने कुछ शीर्ष गोल्फर पैदा किए हैं, जिन्होंने दुनिया भर के टूर्स में खेला और जीता है। भारत में गोल्फ को अभी भी एक अभिजात्य खेल माना जाता है और लाहिड़ी ने कहा कि टोक्यो में 23 वर्षीय अदिति के प्रदर्शन से देश में खेल के पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव आना चाहिए।

दुनिया की 200वें नंबर की खिलाड़ी अदिति ने फाइनल राउंड में 3 अंडर 68 का कार्ड बनाकर 15-अंडर का संयुक्त स्कोर दर्ज किया और एक शॉट से पदक के स्थान से चूक गईं। भारत के नंबर-1 पुरुष गोल्फर लाहिड़ी ने अदिति के प्रदर्शन की सराहना की और कहा, मुझे उम्मीद है कि यह लोगों के रवैये में बदलाव लाएगा और गोल्फ एक खेल के रूप में भारत में किसी भी अन्य ओलंपिक खेल की तरह विकसित हो सकता है।

लाहिड़ी ने ओलम्पिक डॉट कॉम से कहा, अदिति के लिए सबसे बड़ी जीत यह है कि अब बहुत से भारतीय जानते हैं कि गोल्फ क्या है, यह कैसे काम करता है। और फिर, वास्तव में भारत में गोल्फ को मानचित्र पर रखते हुए, मुझे लगता है कि यह वास्तव में गोल्फ के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

लाहिड़ी ने कहा कि टोक्यो में अदिति का फाइनल राउंड देखने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय शनिवार को जल्दी उठ गए, यह खेल के लिए एक बड़ी जीत थी। लाहिड़ी ने महसूस किया कि अदिति का प्रदर्शन पूरी पीढ़ी को इस खेल को अपनाने और बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित करेगा। वह बोले, मुझे लगता है कि यह शानदार है। अदिति ने बिल्कुल अविश्वसनीय गोल्फ खेला। उन सभी चुनौतियों को देखते हुए जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता, मंच को देखते हुए बहुत सारे लोग चाहते थे कि वह अच्छा करे। उसने शानदार प्रदर्शन किया है। यह गोल्फ के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा।

नीरज चोपड़ा को दो करोड़ और अन्य पदक विजेताओं को एक-एक करोड़ देगा बायजूस

नई दिल्ली, 8 अगस्त (एजेंसियां)। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रायोजक बायजूस ने टोक्यो ओलम्पिक के स्वर्ण विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को दो करोड़ रुपये और अन्य व्यक्तिगत पदक विजेताओं को एक करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारत ने टोक्यो में कुल सात पदक जीतकर इन खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर डाला है। बायजूस कल स्वर्ण जीतने वाले नीरज को दो करोड़ रुपये देने के अतिरिक्त मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया , लवलीना बोर्गोहैन , पीवी सिंधू और बजरंग पुनिया को एक-एक करोड़ रुपये देगा।

बायजूस के संस्थापक और सीईओ बायजू रवींद्रन ने रविवार को यह घोषणा करते हुए कहा, राष्ट्र निर्माण में खेलों की भूमिका महत्वपूर्ण है और यह समय है कि हम अपने ओलम्पिक हीरोज की उपलब्धियों का जश्न मनाएं। चार वर्षों में एक बार नहीं बल्कि हर रोज। हम खिलाड़ियों को उनकी मेहनत, त्याग और उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत कर रहे हैं।

बुमराह ने नीरज को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर दी बधाई

नॉटिंघम, 8 अगस्त (एजेंसियां)। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। नीरज ने शनिवार को 87.58 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता था। नीरज भारतीय निशानेबाज अभिन्व बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय एथलीट बने, जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीता है।

बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, जब हम लंच के लिए अंदर आए और हमें पता चला कि यह फाइनल था तो उन्हें बहुत-बहुत बधाई। ओलंपिक में भाग लेना ही बड़ी उपलब्धि है। देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी होती है। उन्होंने कहा, ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीतना एक बड़ी उपलब्धि है। हम सभी उनके लिए काफी खुश हैं। भारतीय क्रिकेट लोकेश राहुल ने पहलवान बजरंग पुनिया के कांस्य पदक

जीतने पर कहा, आप एक शेर की तरह लड़े और अपना बेस्ट दिया। बजरंग को कांस्य पदक जीतने पर बधाई।

भारतीय हॉकी टीमों ने हासिल की अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग

नई दिल्ली, 8 अगस्त (एजेंसियां)। टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक स्वप्निल अभियान के बाद भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने अपनी सर्वोच्च एफआईएच विश्व रैंकिंग हासिल कर ली है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, जिसने टोक्यो में कांस्य पदक जीतकर 41 साल के पदक के सूखे को समाप्त किया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग में क्रमश- तीसरे स्थान पर पहुंच गई जबकि, भारतीय महिला हॉकी टीम नवीनतम एफआएच विश्व रैंकिंग के अनुसार 8वें स्थान पर पहुंच गई है।

इस उपलब्धि से पहले, मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम की करियर-उच्च रैंकिंग नंबर-4 थी, जिसे उन्होंने मार्च 2020 में एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2020 के दूसरे संस्करण के पहले तीन राउंड में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर हासिल किया था।

दूसरी ओर, भारतीय महिला टीम की अब तक की सर्वोच्च विश्व रैंकिंग 9वीं थी, जिसे उन्होंने चार दशकों में विटैलिटी हॉकी

सर्वश्रेष्ठ फिनिश (क्वार्टर फाइनल) कर पूरा किया था। विश्व कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के बाद, भारतीय टीम शीर्ष क्रम की एशियाई टीम बन गई और जकार्ता पालेमबांग 2018 एशियाई खेलों में रजत

दोनों टीमों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद अपनी सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की। मनप्रीत एंड कंपनी पूल ए में ग्रुप चरण के पांच मैचों में से चार मैच जीतकर दूसरे स्थान पर रही से हराया लेकिन सेमीफाइनल में बेल्जियम से 5-2 से हार गई। उसने हालांकि ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल करने के लिए जर्मनी पर 5-4 से जीत की।

पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची महिला हॉकी टीम

भरत की महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची थी। टीम अपने ग्रुप में चौथे नम्बर पर रही थी और अंतिम आठ में स्थान बनाया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियां को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाबी पाई थी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दी थी। जिसके बाद टीम से पदक की उम्मीद थी लेकिन भारत अपने अंतिम दो मैच करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। यकीनन सबसे बड़ा उलटफेर उस समय हुआ जब वह क्वार्टर फाइनल में पहुंची और विश्व नंबर 3 ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया। रानी एंड कंपनी क्रमश: अर्जेंटीना और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ सेमीफाइनल और कांस्य पदक प्ले-ऑफ मैच दोनों हार गई।

इस तरह, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने से भारत की महिला हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गई।

सार संक्षेप

सर्बिया ने जीता पुरुष वाटर पोलो का स्वर्ण

टोक्यो। सर्बिया ने टोक्यो ओलम्पिक की आखिरी प्रतियोगिता पुरुष वाटर पोलो का स्वर्ण पदक यूनान को रविवार को 13-10 से हराकर जीत लिया। जाकसिच, डुस्को पिजेतलोविच और फिलिप फिलिपोविच के दो-दो गोलों से पहले क्वार्टर में 6-3 की बढ़त बना ली। यूनान ने वापसी करते हुए दो क्वार्टर के बाद स्कोर 8-7 कर दिया और फिर आखिरी क्वार्टर में जाते-जाते स्कोर10-9 कर दिया। सर्बिया इन प्रयासों के बाद संभला और जाकसिच ने एक और गोल कर दिया और फिर अपना डिफेंस मजबूत करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया इससे पहले हंगरी ने स्पेन को 9-5 से हराकर कांस्य पदक जीता।

फ्रांस ने जीता महिला हैंडबॉल का स्वर्ण

फ्रांस ने रूसी ओलम्पिक समिति की टीम को रविवार को टोक्यो ओलम्पिक के आखिरी दिन 30-25 से हराकर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया। फ्रांस ने इस जीत के साथ रियो में पिछले ओलम्पिक के फ़ाइनल में मिली हार का बदला भी चुका लिया। फ्रांस ने दोनों हाफ 25-12 और 25-13 के अंतर से जीते। फ्रांस की जीत में पौलेटा फ़ोप्पा का महत्वपूर्ण योगदान रहा जिन्होंने अपने सभी सात प्रयासों को गोल में बदला। एलिसन पिनियु ने भी सात गोल दागे। रूस के लिए पोलिना वेदेखिना ने भी सात गोलों का योगदान दिया। रियो 2016 में कांस्य पदक जीतने वाले नॉर्वे ने स्वीडन को 36-19 से हराकर फिर कांस्य पदक जीता।

नीरज को दो करोड़ देगी पंजाब सरकार

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक्स में एथलेटिक्स मुकाबलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए दो करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सभी भारतीयों और पंजाबियों के लिए गौरव का क्षण है। भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात नीरज के परिवार की जड़ें पंजाब में हैं।

वॉलीबॉल : अमेरिका ने ब्राजील को हराकर स्वर्ण पदक जीता

टोक्यो। अमेरिका ने रविवार को यहां महिला वॉलीबॉल फाइनल में ब्राजील को 3-0 से हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। बीजिंग 2008 और लंदन 2012 में लगातार दो बार ओलंपिक फाइनल में ब्राजील से हारने वाली अमेरिकी महिलाओं को आखिरकार ब्राजील को 25-21, 25-20 और 25-14 से हराकर पहली बार ताज पहनने का गौरव हासिल किया। एंड्रिया ड्रूज 15 अंकों के साथ अमेरिका की सबसे सफल खिलाड़ी रहीं जबकि इसके अलावा मिशेल बार्टश-हैकले और लार्सन ने क्रमश- 14 और 12 अंक जोड़े। तंदरा कैक्सेटा के बिना खेलना, जिन्हें संभावित डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, ब्राजील का नेतृत्व फर्नांडा रोड्रिग्स ने किया।